घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 194- शनिवार 16 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता

5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा,7 विषयों पर सहमति...

दुबई,15 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। अबूधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के एफ-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। नरेन्द्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान 7 अहम विषयों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की।

मोदी बोले- यह यात्रा छोटी लेकिन उपयोगी रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरा खत्म होने पर कहा कि उनकी यह छोटी लेकिन बेहद उपयोगी यात्रा रही। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस दौरे के नतीजे दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत-यूएई रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा, 'भारत और यूएई की दोस्ती बहुत मजबूत है। मोदी ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।

मोदी बोले...भारत-यूएई साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंची : मोदी ने कहा कि जनवरी में यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि कम समय में दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में तेज प्रगति की है। मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत-यूएई रणनीतिक सहयोग का महत्व और बढ़ गया है।

पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति की मौजूदगी में कई एमओयू साइन

पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति अल नाहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच कई अहम एमओयू और समझौतों का आदान-प्रदान हुआ। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई से जुड़ा अहम समझौता भी हुआ है। समझौते रक्षा, ऊर्जा, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी एमओयू साइन किया गया। वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर दोनों देशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की।

मोदी बोले...भारत के लिए संवेदना जताने पर धन्यवाद

मोदी ने भारत में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताने के लिए धन्यवाद अल नाहयान को दिया। बैठक में मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों में भारत में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए आपने संवेदना व्यक्त की। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मोदी बोले...होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना जरूरी

मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है और भारत हमेशा संवाद व कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी रहेगा।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की विवादित भोजशाला को मंदिर घोषित किया

मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज..

भोपाल,15 मई 2026। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की विवादित भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताया है। सुनवाई के दौरान हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदायों के याचिकाकर्ताओं ने दलीलें पेश कीं और स्मारक में अपने-अपने समुदाय के लोगों के लिए उपासना का विशेष अधिकार मांगा। फिलहाल यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नियंत्रण में है। हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा, ऐतिहासिक साहित्य स्थल विवाद के चरित्र को स्थापित करते हैं कि ये क्षेत्र भोजशाला था,जो परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। क्षेत्र का धार्मिक चरित्र वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के साथ भोजशाला माना जाता है। पीठ 2003 के एएसआई के उस आदेश को रद्द करती है,जो परिसर में पूजा करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है और मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अगर प्रतिवादी धार के भीतर भूमि आवंटन या मस्जिद के निर्माण के लिए आवेदन

प्रस्तुत करता है, तो राज्य आवेदन पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने विवादित भोजशाला का संरक्षण एएसआई को देते हुए कहा, याचिकाकर्ता द्वारा देवी सरस्वती की मूर्ति को लंदन संग्रहालय से लाकर भोजशाला परिसर में स्थापित करने के लिए राहत का दावा किया गया है। सरकार इस पर विचार कर सकती है। धार में 800 साल पुरानी भोजशाला को लेकर हिंदू-मुस्लिम के बीच विवाद है। हिंदू इसे सरस्वती मंदिर,जबकि मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। हिंदू संगठन बताते हैं कि राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला में सरस्वती सदन 1,000 वर्ष पूर्व शिक्षा का बड़ा संस्थान था।

पेट्रोल-डीजल तीन रुपये प्रति लीटर हुआ महंगा

नई दिल्ली,15 मई 2026। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सीएनजी के दाम भी दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। करीब चार साल बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में भी ईंधन की कीमतों में उछाल आया है। कोलकाता में पेट्रोल 3.29 रुपये बढ़कर अब 108.74 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 3.14 रुपये बढ़कर 106.68 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। दक्षिण भारत के बड़े शहर चेन्नई में पेट्रोल के दामो में 2.83 रुपये का उछाल आया है और नई कीमत 103.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में डीजल की कीमत में 3.11 रुपये का इजाफा हुआ है। वहां एक लीटर डीजल 95.13 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में भी डीजल 3.11 रुपये महंगा होकर 93.14 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चेन्नई में डीजल की कीमत में 2.86 रुपये का इजाफा किया गया है। वहां डीजल अब 95.25 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली के प्रीत विहार स्थित भारत पेट्रोलियम के पंप पर एक ग्राहक ने इस पर कहा, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?

डीजल-पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर खरगे ने मोदी सरकार को घेरा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पांच राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। खरगे ने जनता की जेब पर बढ़ते बोझ को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्क फ्रॉम होम और तेल बचाने की नसीहत पर खरगे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये संकट मोदी सरकार द्वारा निर्मित संकट है। मोदी सरकार में दूरदर्शी सोच का अभाव है, इसे जनता को समझना चाहिए। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में वृद्धि उद्योगों से लेकर घरेलू बजट और किसानों पर भी पड़ रहा है। खरगे ने कहा कि चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष को सब सामान्य नजर आता है लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब जगह संकट फैल जाता है, मंहगाई चरम पर पहुंच जाती है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी बोले...'गलती सरकार की,कीमत जनता चुकाएगी'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की गलती की कीमत जनता चुकाएगी। राहुल गांधी ने भविष्य में भी तेल कीमतों में इजाफा होने की आशंका व्यक्त की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'गलती सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका,बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी।'

रामेश्वरम मंदिर में लड्डू घोटाला

मुफ्त प्रसाद बेचकर 3.40 करोड़ की धोखाधड़ी,छह कर्मचारी निलंबित

रामनाथपुरम,15 मई 2026। अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं को मुफ्त वितरित किए जाने वाले लड्डू प्रसाद को अवैध रूप से बेचकर 3 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मंदिर प्रशासन ने एक जूनियर असिस्टेंट सहित छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पिछले मार्च महीने में मंदिर के संयुक्त आयुक्त सेलतुरई ने लड्डू प्रसाद की तैयारी और आय-व्यय खातों की अचानक जांच कराई। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्राथमिक जांच में पता चला कि प्रसाद निर्माण और बिक्री के प्रभारी जूनियर असिस्टेंट के. पंचमूर्ति ने मुफ्त बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या रिकॉर्ड में कम दिखाकर उन्हें स्टॉलों के माध्यम से अवैध रूप से बेच दिया। इसके जरिए बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों और अन्य स्टाफ से लगातार पूछताछ की गई। जांच में यह पुष्टि हुई कि जूनियर असिस्टेंट के. पंचमूर्ति के नेतृत्व में कर्मचारियों का एक समूह लंबे समय से इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी बाजार से कच्चा माल थोक में खरीदकर अवैध तरीके से लड्डू तैयार किए गए और उन्हें मंदिर परिसर के काउंटरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को बेचा गया।

कर्नाटक के कोप्पल में तुंगभद्रा पुल पर हादसा,छह लोगों की मौत,दस से अधिक घायल

कोप्पल,15 मई 2026। कर्नाटक के कोप्पल जिले के मुनिराबाद के पास स्थित तुंगभद्रा पुल पर शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दस से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मुनिराबाद थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया। मृतकों की पहचान केंचप्पा (35), महांतेश (18), भरत (1), सविता (12), मारेश और गौरम्मा के रूप में हुई है। सभी मृतक विजयनगर जिले के कूडलिगी तालुक के मरलायनहल्ली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, श्रद्धालु हुलिगेम्मा जात्रा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक टैंकर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत होस्पेट और कोप्पल जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है।

NEET परीक्षा की नई तारीख का ऐलान..

21 जून को होगी,नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी

नई दिल्ली,15 मई 2026। अगले सत्र से नीट-यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट-यूजी-2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए। इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था।

एनटीए ने सरकार को बताया। फिर 12 मई को रीएग्जाम का फैसला लिया गया।' शिक्षा मंत्री ने कहा, 'रीएग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र रीएग्जाम में अपनी पसंद का

सेंटर चुन पाएंगे।' इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई था। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के आने-जाने के लिए राज्यों से बात करूंगा : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद यह उल्लंघन कैसे हुआ। ऐसे में सरकारी मशीनरी यह सुनिश्चित करेगी कि इस बार कोई अनियमितता न हो। मंत्री के रूप में, अभिभावक के रूप में, अधिकारी के रूप में हमें परीक्षा रद्द करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें सुधारों के लिए कई सुझाव मिले हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। एनटीए का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था। इसके अलावा मैं उम्मीदवारों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से बात करूंगा। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 यानी राजस्थान से पकड़े गए मांगी लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने इनके अलावा, पुणे से ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे, नासिक से धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया था।

समय से 6 दिन पहले मानसून पहुंचेगा केरलम, 26 मई से झमाझम बारिश

नई दिल्ली,15 मई 2026। भारतीय मौसम विभाग ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे केरलम समेत दक्षिण भारत के राज्यों को शुक्रवार को राहत भरी खबर सुनाई है। विभाग ने बताया कि इस साल केरलम में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून समय से 6 दिन पहले 26 मई को पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक, अनुमानित तिथि 26 मई है, लेकिन यह 4 दिन आगे-पीछे होकर 22 से 30 मई के बीच आ सकता है। केरलम में आमतौर पर मानसून 1 जून को आता है। आईएमडी ने बताया कि 2005 से 2025 के बीच पिछले 21 सालों में केरलम में मानसून की तारीख के बारे में आईएमडी के अनुमान सही साबित हुए। सिर्फ 2015 में अनुमान गलत था। पिछले साल मानसून के आगमन का अनुमान 27 मई को था, जबकि आया 24 मई को, इसके पहले 2024 में

अनुमान 31 मई को था, जबकि आया 30 मई को था। वर्ष 2020, 2021 और 2023 में मानसून क्रमशः एक, 3 और 8 जून को आया था। भारत के अलग-अलग राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की पहचान केरलम में मानसून आने से होती है, जो गर्म और शुष्क मौसम से बरसात के राहत भरे मौसम में ले जाता है। केरलम में 26 मई तक बारिश शुरू होगी तो मानसून कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी समय से पहले पहुंचेगा।

पीएम मोदी सलाह देकर विदेश चले गए : भूपेश

बीजेपी संगठन में बदलाव पर कहा...दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंके गए बृजमोहन-रामविचार

दुर्ग-भिलाई,15 मई 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में कहा कि पेट्रोल-डीजल के संकट बीच पीएम मोदी सलाह देकर विदेश चले गए। उन्होंने कहा कि फ्यूल स्टेशनों पर कतारें लगी हुई है। कई पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हैं और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सुशासन त्योहार बना रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह स्थिति वैसी ही है, जैसे कोरोना काल में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी के संगठनात्मक फेरबदल पर पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने अपने पुराने नेताओं को दूध की मक्खी

की तरह निकालकर फेंक दिया है। उन्होंने कृषि मंत्री और रायपुर सांसद का नाम लेते हुए कहा कि कोर कमेटी ने न रामविचार नेताम हैं,न बृजमोहन हैं। भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को नंबर देने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में सरकार चला कौन रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा है कि शासन मंत्रिमंडल चला रहा है या अधिकारी।

कांकेर में 6.5 लाख के नकली नोटों साथ पकड़ाया युवक

नशे और कर्ज में डूबा,घर में ही छापने लगा 500-500 के जाली नोट

कांकेर,15 मई 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नशे और कर्ज में डूबा युवक घर में ही नकली नोट छापने लगा। पुलिस ने लगभग 6.5 लाख के नकली नोटों के साथ आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने 500-500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही प्रिंटर,लैपटॉप और स्कैनर भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था और जल्दी पैसा कमाने के लिए उसने नकली नोट छापने की साजिश रची। किसी ने सूचना दी कि बस स्टैंड पर युवक नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है आरोपी के पहले

भी मार्केट में नकली नोट खपाने की आशंका है। उसने अब तक कितने नकली नोट मार्केट में खपाए हैं? उसके साथ और कौन-कौन शामिल है? इसकी जांच की जा रही है। आरोपी यह काम पिछले 5-6 महीनों से कर रहा था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड इलाके में एक युवक बड़ी मात्रा में नकली नोट लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से 500 रुपए के कई नकली नोट बरामद हुए।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। कर्ज में डूबा हुआ था और जल्दी पैसा कमाने के लिए उसने नकली नोट छापने की योजना बनाई थी। वह पिछले 5 से 6 महीने से घर पर ही प्रिंटर और स्कैनर की मदद से इन नोटों को छापता था। पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारकर नकली नोट छापने में इस्तेमाल किए गए प्रिंटर, लैपटॉप और स्कैनर भी जब्त कर लिए हैं।

संपादकीय

समय रहते चेतें

इस तथ्य पर हैरानी नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेलों के आयात में भी अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों के सेवन में कमी लाने की भी अपील की। उनका यह कहना सही है कि इससे सेहत सुधारने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता मिलेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत अपनी जरूरत भर का तिलहन क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है?

यह सामान्य बात नहीं कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। पिछले वर्ष खाद्य तेल आयात बिल करीब 20 अरब डालर का था। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि कृषि प्रधान देश होने और आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर बल देने के बाद भी देश में तिलहन फसलों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है,जितना अपेक्षित है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके चलते उनके उत्पादन में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिली है, लेकिन इसी के साथ खाद्य तेल की मांग और खपत भी बढ़ रही है।

ऐसा इसलिए हो रहा है,क्योंकि जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, उनके खानपान में तेलों की खपत बढ़ रही है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि जब संकट सामने आ खड़ा होता है, तब उससे बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाता है। खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का सघन अभियान तो बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था और उसकी लगातार समीक्षा भी की जानी चाहिए थी।

बात केवल खाद्य तेलों की ही नहीं है,भारत को बड़ी मात्रा में दालों का भी आयात करना पड़ता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। कहना कठिन है कि दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए? जो भी हो, यह सही समय है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य आयातित वस्तुओं में कमी लाने के ठोस एवं दीर्घकालिक उपाय करे।

यह सही है कि भारत में कच्चे तेल के अपेक्षित भंडार नहीं, इसलिए उसका आयात करना ही होगा, लेकिन आखिर हर तरह के ईवी वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए कोई आकर्षक प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं लाई जा पा रही है और उनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार द्रूत गति से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी तरह क्या कारण है कि किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है कि छोटे-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोल एवं डीजल की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?

कब तक दोहराई जाती रहेंगी निर्भया जैसी त्रासदियां?

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

दिल्ली के नांगलोई में एक निजी बस के भीतर महिला के साथ हुई बस कंडक्टर एवं ड्राइवर के दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं,बल्कि उस भयावह सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का आईना है,जो वर्षों से हमारे सामने खड़ी है। चौदह वर्ष पहले निर्भया कांड के बाद देश की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था। लोगों ने सोचा था कि अब व्यवस्था बदलेगी,कानून सख्त होंगे,महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समाज अपनी सोच बदलेगा। लेकिन आज जब उसी प्रकार की घटनाएं पुनः पुनः सामने आती हैं,तब यह प्रश्न और भी तीखा होकर उठता है कि आखिर हम बदले कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसका उत्तर केवल कानून की कमजोरी में नहीं,बल्कि समाज की उस विकृत मानसिकता में छिपा है,जहां महिला को आज भी बराबरी के सम्मान के साथ नहीं देखा जाता। आधुनिकता के चमकदार दावों के बीच भी पुरुष प्रधान सोच का अंधेरा जस का तस मौजूद है। महिलाओं को व्यक्ति नहीं,बल्कि उपभोग की वस्तु मानने वाली सोच आज भी अनेक मन-मस्तिष्कों में गहराई तक बैठी हुई है। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, स्कूल-कॉलेजों और यहां तक कि घरों के भीतर भी महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं।

विडंबना यह है कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के इस दौर में भी समाज स्त्री के सम्मान और सुरक्षा के बुनियादी संस्कार विकसित नहीं कर पाया। बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन संवेदनाएं नहीं दी जा रहीं। घरों में बेटियों पर नियंत्रण और बेटों को छूट देने वाली मानसिकता आज भी कायम है। एक ओर ले कियों को सावधान रहने की नसीहत दी जाती है, दूसरी ओर लड़कों को अपने व्यवहार और दृष्टि की मर्यादा सिखाने की गंभीर कोशिश बहुत कम दिखाई देती है। यही असंतुलन आगे चलकर अपराधों की जमीन तैयार करता है। प्रश्न यह भी है कि प्रशासन बार-बार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों हो रहा है? निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्पलाइन,फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस गश्त और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों की लंबी घोषणाएं हुईं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन व्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया। निजी बसें आज भी बिना पर्याप्त निगरानी के चल रही हैं। कई स्थानों पर चालक और परिचालकों का समुचित सत्यापन तक नहीं होता। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है।

दुनियाभर में बालिकाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिये जागरूकता एवं आन्दोलनों के बावजूद बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है, बालिकाओं की स्थिति,लड़कियों की तुलना में लड़कों की बढ़ती संख्या, तलाक के बढ़ते मामले,गांवों में बालिका की अशिक्षा, कुपोषण एवं शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा, बालिकाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं,अश्लील हरकतें और विशेष रूप से उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी चर्चा एवं कठोर निर्णयों से एक सार्थक वातावरण

का निर्माण किये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि एक टीस-सी मन में उठती है कि आखिर महिलाएं एवं बालिकाओं कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? बलात्कार,छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौचा जाता रहेगा?

सच्चाई यह है कि हमारी व्यवस्था अपराध होने के बाद सक्रिय होती है, अपराध रोकने के लिये नहीं। हर बार घटना के बाद गिरफ्तारी, जांच और बयानबाजी होती है,लेकिन अपराध की जड़ों तक पहुंचने की गंभीर पहल नहीं दिखाई देती। राजनीतिक दल कुछ दिनों तक आरोप-प्रत्यारोप करते हैं,मीडिया में बहस चलती है और फिर धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जिन परिवारों की बेटियां इस अमानवीयता का शिकार होती हैं, उनके जीवन में भय,पीड़ा और असुरक्षा स्थायी घाव बनकर रह जाते हैं। यह भी विचारणीय है कि आखिर महिलाएं और बालिकाएं बार-बार ऐसे अत्याचारों का शिकार क्यों बन रही हैं? इसका कारण केवल अपराधियों की क्रूरता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता भी है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है। लोग तमाशबीन बन जाते हैं। कई बार पीड़िता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है-उसके कपड़े, समय, जीवनशैली और व्यवहार पर सवाल उठाए जाते हैं। यह मानसिकता अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समाज पूरी तरह पीड़िता के साथ खड़ा नहीं होगा। कब तक महिलाएं अपने ही शहरों,बसों,गलियों और कार्यस्थलों पर भय के साथ जीती रहेंगी? कब तक माता-पिता अपनी बेटियों के घर लौटने तक चिंता में डूबे रहेंगे? यह प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं,बल्कि पूरे समाज की आत्मा का प्रश्न है। जिस समाज में आधी आबादी स्वयं को सुरक्षित महसूस न करे, वह समाज वास्तव में सभ्य नहीं कहलाया जा सकता।

आज आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं,बल्कि कठोर सामाजिक आत्ममंथन की है। कानून अपराधी को दंड दे सकता है,लेकिन समाज ही मानसिकता बदल सकता है। स्कूलों और परिवारों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बेटियों को भय में जीना नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीना सिखाना होगा। फिल्मों,सोशल मीडिया और विज्ञापनों में स्त्री की वस्तुवादी छवि पर भी गंभीर विमर्श जरूरी है,क्योंकि संस्कृति और मनोरंजन भी समाज की सोच को प्रभावित करते हैं। प्रशासन को भी केवल घटनाओं के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में रियल-टाइम जीपीएस,सीसीटीवी,पैनिक बटन और नियमित निगरानी को पूरी कठोरता से लागू करना होगा। निजी परिवहन संचालकों और कर्मचारियों का गहन सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदन शील,जवाबदेह और सक्रिय बनाना होगा।सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाज को यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा कोई महिला मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता और सभ्यता का प्रश्न है। जब तक स्त्री को समान सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं मिलेगी,तब तक विकास के सारे दावे अधूरे रहेंगे।

नांगलोई की यह घटना केवल एक समाचार नहीं,बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। यदि अब भी हम नहीं जागे,तो निर्भया जैसी त्रासदियां बार-बार हमारे सामने आती रहेंगी और हर बार हमारी संवेदनहीनता,हमारी प्रशासनिक विफलता और हमारी विकृत मानसिकता हमें कठघरे में खड़ा करती रहेगी। प्रश्न यही है-आखिर कब तक? तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में भी बालिकाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। धर्मगुरु, राजनेता एवं समाजसुधारक महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति कितनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते आए हैं,यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। इनके चरित्र का दोहरापन जगजाहिर हो चुका है। कोई क्या पहने, क्या खाए,किससे प्रेम करे और किससे शादी करें,सह-शिक्षा का विरोधी नजरिया- इस तरह की पुरुषवादी सोच के तहत बालिकाओं को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है,उन पर तरह-तरह की बंदिशें एवं पहरे लगाये जा रहे हैं।'यत्र पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता'-जहां नारी की पूजा होती है,वहां देवता निवास करते हैं। किंतु आज हम देखते हैं कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे 'भोग की वस्तु'समझकर आदमी'अपने तरीके' से'इस्तेमाल'कर रहा है,यह बेहद चिंताजनक बात है। आज अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं शक्ल बदल-बदल कर काले अध्याय रच रही है। देश में गैंगरेप की वारदातों में कमी भले ही आयी हो, लेकिन उन घटनाओं का रह-रह कर सामने आना त्रासद एवं दुःखद है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

प्राचीन भारत के लोक-कल्याण का ताम्र-साक्ष्य है गोरखपुर का सोहगौरा अभिलेख

दुर्गेश्वर राय,
गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर जब गौरवशाली प्राचीनतम शासन व्यवस्था और लोक-कल्याणकारी नीतियों के अगणित अध्याय अंकित हैं। सम्राट अशोक और शेरशाह की सड़क परिवहन और औषधालय व्यस्था हो या शिवाजी का भूमि स्वामित्व व्यस्था हो या कृष्णदेव राय का जल प्रबंधन हो या सयाजीराव गायकवाड़ की पहली निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यस्था हो;लोक-कल्याण के कार्यों को एक साथ सूचीबद्ध करने बैठे तो कोई न कोई सिरा छूट ही जाएगा। समय-समय पर इन कार्यों के पुष्टि के रूप में विविध प्रकार के साक्ष्य मिलते रहे और इतिहासकारों के कसौटी पर परखे जाने के पश्चात इतिहास में दर्ज होते रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की मिट्टी ने अपने गर्भ में एक ऐसा अमूल्य साक्ष्य सँजोकर रखा था,जिसने मौर्यकालीन भारत की प्रशासनिक दूरदर्शिता को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। यह साक्ष्य है'सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख'।

सोहगौरा,जो वर्तमान गोरखपुर जनपद की बाँसगाँव तहसील में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव है,19वीं सदी के अंत तक अपनी इस महान विरासत से अनजान था। इस धरोहर को दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉ. ए.सी.एल. कार्लाइल को जाता है। साल 1893-94 के दौरान,जब कार्लाइल इस क्षेत्र के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर थे तब उन्हें इस टीले से यह विलक्षण ताम्रपत्र मिला। उस समय यह कल्पना करना भी कठिन था कि तांबे की यह एक छोटी सी प्लेट,जिस पर कुछ रहस्यमयी आकृतियाँ और अक्षर खुदे हुए हैं,मौर्य साम्राज्य के सामाजिक और प्रशासनिक ढाँचे को समझने की सबसे बड़ी कुंजी बन जाएगी। डॉ. फ्लीट और डॉ. बूलर जैसे दिग्गज लिपि शास्त्रियों ने जब इसका अध्ययन किया, तब इसके ऐतिहासिक अर्थ पहली बार दुनिया के सामने आए।

अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह अभिलेख मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसकी बनावट और अक्षरों की शैली के आधार पर इसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल के आसपास का माना जाता है। डॉ. डी.सी. सरकार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडियन एपिग्राफी'में इसे भारतीय अभिलेख शास्त्र का एक अनूठा उदाहरण माना है।

ताम्रपत्र के शीर्ष पर कुछ विशेष चिन्ह बने हुए हैं, जिनमें पर्वत, वृक्ष और मचाननुमा संरचनाएं शामिल हैं। इतिहासकारों ने जब इन चित्रों का बारीकी से विश्लेषण किया,तो पाया कि ये उन कोष्ठागारों या अनाज के गोदामों के नक्शे थे जिनका वर्णन नीचे दिए गए लेख में किया गया था। डॉ.राजबली पाण्डेय जैसे विद्वानों ने इसके प्रतीकों को तत्कालीन वास्तुकला से जो कर देखा है।

सोहगौरा ताम्रपत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका विषय है। यह अभिलेख किसी राजा की विजय गाथा नहीं है। यह एक सरकारी आदेश है। इसमें श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख है। लेख बताता है कि वंशग्राम जो वर्तमान में बाँसगाँव है और उसके आसपास के तीन प्रमुख स्थानों पर विशाल कोष्ठागार बनाए गए हैं। अभिलेख में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन गोदामों में सुरक्षित रखा गया अनाज केवल अकाल या अत्यंत संकट के समय ही जनता के बीच वितरित किया जाना चाहिए। यह आज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे प्राचीनतम रूप है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले भी भारतीय शासक अकाल जैसी आपदाओं के प्रति इतने सजग थे कि वे पहले से ही बफर स्टॉक तैयार रखते थे।

खोजे जाने के बाद इस ताम्रपत्र का कई दशकों तक गंभीर अकादमिक अध्ययन हुआ। इसकी महत्ता को देखते हुए इसे गोरखपुर से लखनऊ ले जाया गया। वर्तमान में यह ऐतिहासिक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित है। लखनऊ के बनारसी बाग परिसर में स्थित इस संग्रहालय के पुरातत्व अनुभाग में जाकर कोई भी इस कालजयी लेख का अवलोकन कर सकता है।

आज जब हम आधुनिक तकनीक और आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो सोहगौरा का यह छोटा सा ताम्रपत्र हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज इन चुनौतियों से निपटने में हमसे कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यवस्थित दृष्टि रखते थे। गोरखपुर की इस महान थाती वास्तव में भारतीय संस्कृति की उस संवेदना का प्रतीक है जहाँ राजा ने प्रजा को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनके लिए भोजन व्यवस्था को ही अपना सर्वोपरि धर्म माना था। लखनऊ के संग्रहालय में रखा यह ताम्रपत्र हर भारतीय को अपनी जड़ों पर गर्व करने का एक ठोस आधार प्रदान करता है। यह हमारे गौरवशाली प्रशासनिक इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे समय की धूल भी धुंधला नहीं कर पाई।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

नदी नहीं,अपनी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों को बचा रहे हैं श्रमवीर

धूप में तपते फावड़े और सपनों से सींची जा रही है बेतवा की जीवनधारा

बेतवा पुनर्जीवन का महाअभियान –श्रम,संकल्प और जनचेतना से लौट रही जीवनधारा

प्रो. आरके जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

अनादि काल से जनजीवन, संस्कृति और सभ्यता को जीवनरस प्रदान करने वाली वेत्रवती आज पुनर्जागरण की दिव्य चेतना बनकर पुनः जाग उठी है। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के झिरी (कुम्हारा) गांव में स्थित पावन उद्गम क्षेत्र में 10 मई 2026 से आरम्भ श्रमदान सप्ताह-2026 केवल स्वच्छता या संरक्षण का अभियान नहीं, बल्कि मृतप्राय होती प्रकृति में नवजीवन संचारित करने का विराट लोकयज्ञ बन चुका है। उपेक्षा,अतिक्रमण, मलबा संचयन और परिवर्तित ऋतुचक्र के प्रहारों से आहत इस तपोभूमि को पुनर्जीवित करने हेतु जनसामान्य प्रखर धूप में भी फावड़ा, टोकरी और अटूट संकल्प के साथ निरंतर श्रमरत है। यह प्रेरक दृश्य उद्घोष कर रहा है कि जब सामूहिक चेतना जागृत होती है,तब सूखी धाराएँ भी पुनः अमृतधारा बनकर प्रवाहित होने लगती हैं। यह महाअभियान केवल जलसंरक्षण का प्रयास नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित अस्तित्व,प्रकृति-संतुलन और जीवन मूल्यों के संरक्षण का सुदृढ़ आधार निर्मित कर रहा है।

सूखी पड़ती जीवनधारा को पुनर्जीवित करने का जो संकल्प गत वर्ष जागा,वही आज इस महाअभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। स्थानीय नागरिकों,पर्यावरण साधकों और सामाजिक संगठनों के श्रम से उद्गम क्षेत्र में 55 लघु चेक डैम / अवरोधक बांध निर्मित किए गए। आरम्भ में यह कार्य असंभव प्रतीत होता था, किंतु सामूहिक संकल्प ने इसे संभव कर दिखाया। इन अवरोध बांधों के कारण बेतवा उद्गम लगभग छह माह तक जलमय रहा तथा जलधारा अविरल बहती रही। यह सफलता केवल निर्माणकार्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि जागृत समाज की उत्तरदायी चेतना का प्रमाण थी। इसी प्रेरणा ने इस वर्ष के श्रमदान सप्ताह को और व्यापक बना दिया है। लोगों ने अनुभव किया कि निष्ठापूर्ण प्रयासों के आगे प्रकृति भी अपना आशीर्वाद देती है। यही विश्वास प्रतिदिन सैकड़ों श्रमसेवियों को उद्गम स्थल तक खींच ला रहा है।

जब समाज स्वयं प्रकृति के संरक्षण का संकल्प उठा लेता है,तब जनशक्ति परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती है। ग्राम सेवा समिति भोपाल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं की प्रेरक सहभागिता दिखाई दे रही है। बेतवा बिरादरी विदिशा,नमन सेवा समिति बैतूल, युवा फाउंडेशन भोपाल, गांधी भवन,सप्रे संग्रहालय,एनजीओ पाठ शाला,स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर तथा मैनिट सहित अनेक संस्थाएं सक्रिय रूप से श्रमदान कर रही हैं। यह सहभागिता सिद्ध करती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक धर्म है। यहां औपचारिकता नहीं,बल्कि मिट्टी और नदी के प्रति आत्मीय समर्पण दिखाई देता है। यही भावना इस अभियान को जनभागीदारी से जनआंदोलन में परिवर्तित कर चुकी है।

जब वृद्ध हाथों का अनुभव और युवाओं का उत्साह एक साथ मिट्टी से जुड़ता है,तब परिवर्तन इतिहास बन जाता है। इस महाअभियान में युवाओं के साथ सत्तर,पचहत्तर और अस्सी वर्ष की आयु पार कर चुके वरिष्ठजन भी अदम्य ऊर्जा से श्रमदान कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी और कठिन श्रम के बीच उनका समर्पण युवा पीढ़ी के लिए जीवंत प्रेरणा बन गया है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ वन अधिकारी श्री आजाद सिंह डबास,श्री कौशलेंद्र सिंह सहित अनेक अनुभवी पर्यावरण साधकों की उपस्थिति ने अभियान को दिशा और निरंतरता प्रदान की है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रकृति के प्रति दायित्व की कोई आयु-सीमा नहीं होती। पीढ़ियों के इस संगम ने यह संदेश भी दिया है कि जब अनुभव और युवा शक्ति साथ खड़े होते हैं, तब जनसंकल्प अजेय बन जाता है।

जब कोई व्यक्ति अपना अनुभव समाज और प्रकृति के पुनर्जागरण को समर्पित कर देता है,तब अभियान जनआस्था बन जाता है। डॉ. आर. के. पालीवाल इस महाअभियान की वही प्रेरक शक्ति हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त रहे डॉ. पालीवाल ने प्रशासनिक जीवन के पश्चात प्रकृति संरक्षण को अपना जीवनसंकल्प बना लिया। उनका श्रम,नेतृत्व और समर्पण अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। वे केवल आह्वान नहीं करते, बल्कि स्वयं फावड़ा उठाकर श्रमदान करते हैं। उनका मानना है कि नदियों की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की रक्षा है। उनके नेतृत्व में यह प्रयास श्रमदान से आगे बढ़कर पर्यावरणीय जनचेतना का आंदोलन बन चुका है। उनका जीवन संदेश देता है कि सेवानिवृत्ति अंत नहीं, बल्कि लोकसेवा का नया अध्याय है।

तपती धूप और कठिन परिस्थितियां भी श्रमसेवियों के उत्साह को डिगा नहीं सकीं। लगभग एक दर्जन समर्पित कार्यकर्ता प्रतिदिन सुबह आठ बजे से निरंतर श्रम में जुटे रहे। गत वर्ष निर्मित 55 अवरोध बांधों की मरम्मत के साथ 30 से अधिक नए अवरोध बांध भी तैयार किए जा चुके हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि उस सर्वोच्च पार्वती कुंड का पुनर्जीवन है,जो वर्षों से आठ फीट मलबे में दबा पड़ा था। आज उसी कुंड में एक फीट से अधिक निर्मल जल संचित है,जो वन्य जीवों के लिए जीवनस्रोत बन रहा है। ये उपलब्धियां श्रमसेवियों के समर्पण की सशक्त गवाही हैं और सिद्ध करती हैं कि सामूहिक श्रम से असंभव परिवर्तन भी संभव हो जाते हैं।

बेतवा उद्गम से उठी यह चेतना अब जनजागरण की व्यापक धारा बन चुकी है। स्थानीय सीमाओं से निकलकर यह अभियान दूर-दूर तक लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है। यह केवल समस्याओं का वर्णन नहीं, बल्कि समाधान का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जो लोग प्रकृति को मात्र उपभोग का साधन मानते थे,उनके लिए यह अभियान स्पष्ट संदेश है कि प्रकृति की रक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि श्रम, समय और संवेदना के समर्पण से होती है। जलसंरक्षण के ये प्रयास भविष्य के गहराते जलसंकट के विरुद्ध मजबूत आधार बन सकते हैं। सूखती नदियां केवल जल का संकट नहीं,बल्कि भविष्य के अस्तित्व का चेतावनी संकेत हैं। बेतवा उद्गम पर चल रहा यह श्रमदान सप्ताह किसी एक नदी के पुनर्जीवन तक सीमित नहीं,बल्कि प्रकृति के प्रति राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का सशक्त आह्वान है। समय अब केवल नारों और शब्दों का नहीं,बल्कि धरती के लिए श्रम और समर्पण का है। एक फावड़ा,कुछ पल का श्रम और संरक्षण का संकल्प–यही सुरक्षित भविष्य की वास्तविक पूंजी है। बेतवा पुनर्जीवन का यह महाअभियान सिद्ध कर रहा है कि जब समाज प्रकृति के पक्ष में खड़ा होता है, तब सूखी धरती भी पुनः जीवन से भर उठती है।

सात अपीलें

मोनिका डागा आनंद
चेन्नई,तमिलनाडु

प्यारे देशवासियों से
करबद्ध गुहार फिर एकबार लगाई,
आ. प्रधानमंत्री मोदी जी की सात
अपीलें सामने आई,
समय की मॉग और
सुझबूझ से काम लिया जाए भाई,
वैश्विक खतरे के सकेंत
मंडराते दे रहे हैं हमें दिखाई ।

युद्ध की वज़ह से
तेजी से बढ़ रहे कच्चे तेलों के दाम,
आगामी घड़ी में वित्तीय संकट से
सुरक्षित हो आवाम,
विशेष तैयारी के साथ
करने होंगे कुछ महत्वपूर्ण काम,
अर्थव्यवस्था भी न डगमगाएं
किया जाएं ऐसा इंतजाम ।

ईधन कमी के अनिश्चित
संकट से हताहत पूरा जगत,
डीजल पेट्रोल गैस की करो
बुद्धिमानी से अब बचत,
सोना मत खरीदों विदेशी यात्राओं को
दो विराम सख्त,
खान-पान करो संतुलित
आ गया है संभलने का वक्त ।

जहॉ हो संभव वर्क फ्राम
होम के लिए हो आप तैयार,
मेड इन इंडिया स्वदेशी
उत्पादों के बने ज्यादा खरीदार,
खाद्य तेल में 10 प्रतिशत तक की
कटौती भी होगी असरदार,
सचेत हो अंजाने संकट को
आनंद से कर सकेंगे पार ।

रसायनों का आयात हो कम
प्राकृतिक खेती का निर्णय,
सावधानी हटी दुर्घटना घटी
क्षण में आ सकता है प्रलय,
लड़ने-झगड़ने छींटाकशी का
नहीं हैं ये कीमती समय,
सौ दवा से एक परहेज
अच्छा आपसे है स्नेहमय विनय ।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

CMYK

ई-स्कूटी से दफ्तर पहुंच रहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
देव नारायण यादव ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए अब डीजल-पेट्रोल वाहनों का उपयोग कम कर दिया है। वे इन दिनों ई-स्कूटी से अपने कार्यालय आना-जाना कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी वे ई-स्कूटी और साइकिल से ही सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और कई बड़े मंत्री भी अपने वाहनों के काफिले कम कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और महंगे ईंधन के बीच अब लोगों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। यह समय की जरूरत भी है और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प भी। देव नारायण यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देशहित में अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल का उपयोग करें तथा इस मुहिम से जुड़ें।

इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को नवाचार, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए किया प्रेरित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
तकनीकी शिक्षा में स्क्रीन टाइम के सकारात्मक उपयोग को लेकर संस्था में गुरुवार शाम'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम इन टेक्निकल एजुकेशन' विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती,भारत माता और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पूजा-अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एस. बालकृष्णन उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश साकेत, अनंत सोनी एवं रोहिणी मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे ने की। मुख्य अतिथि एस. बालकृष्णन ने कहा कि तकनीकी शिक्षा केवल स्क्रीन आधारित जानकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,बल्कि इसे नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण से जोडऩा जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग स्टार्टअप,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,रोबोटिक्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट,प्रायोगिक शिक्षा और बहुआयामी अधिगम को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग ई-लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स, समय प्रबंधन और आत्मविकास के लिए करने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि महेश साकेत ने कहा कि तकनीकी शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं,बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वहीं अनंत सोनी ने विद्यार्थियों से अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों के साथ तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने का आह्वान किया।

बसों में लगेज के नाम पर खेल! रायपुर,बिलासपुर, बनारस और रांची रूट पर अवैध सामान ढुलाई का आरोप

यात्रियों की सीटों के नीचे तक भर रहे पार्सल,बिना जांच और बिल के हो रही सप्लाई,टैक्स चोरी की भी आशंका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
रायपुर,बिलासपुर,बनारस और रांची जैसे बड़े शहरों से चलने वाली निजी बसों में इन दिनों यात्रियों से ज्यादा लगेज ढुलाई का कारोबार फल-फूल रहा है। आरोप है कि कई बस संचालक यात्री परिवहन की आड़ में बड़े पैमाने पर पार्सल और संदिग्ध सामान की ढुलाई कर रहे हैं। इस दौरान जीएसटी नियमों की अनदेखी,टैक्स चोरी और अवैध वस्तुओं के परिवहन की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार लंबी दूरी की कई बसों में लगेज बुकिंग का अलग नेटवर्क संचालित हो रहा है। बस स्टैंड और एजेंटों के माध्यम से बिना किसी वैध दस्तावेज और जांच के पार्सल स्वीकार किए जा रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक सामग्री,किराना,दवाइयां और अन्य व्यावसायिक सामग्री तक शामिल होने की बात कही जा रही है। कई मामलों में सामान के साथ जीएसटी बिल या परिवहन दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं रहते।

सीटों के नीचे और छत तक भर रहे पार्सल

यात्रियों का आरोप है कि कई बसों में सीटों के नीचे, गैलरी और डिक्की तक में इतना अधिक सामान भर दिया जाता है कि सफर करना मुश्किल हो जाता है। कुछ बसों में तो यात्रियों के सामान रखने तक की जगह नहीं बचती। बावजूद इसके परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय बसों के जरिए बड़े पैमाने पर पार्सल भेजे जाते हैं। कई बार संदिग्ध पैकेट भी बिना जांच के लोड किए जाते हैं,जिससे अवैध वस्तुओं की ढुलाई की आशंका बनी रहती है। सूत्रों के अनुसार कुछ बस ऑपरेटर लगेज के नाम पर अलग से मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन उसका कोई वैध रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

जीएसटी और परिवहन नियमों पर उठ रहे सवाल

व्यापारिक सामग्री के परिवहन में जीएसटी ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज जरूरी होते हैं,लेकिन आरोप है कि अधिकांश मामलों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे शासन को राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। परिवहन नियमों के अनुसार यात्री बसों में सीमित मात्रा में ही लगेज ले जाने की अनुमति होती है, लेकिन कई बसों में इसे ही मुख्य व्यवसाय बना लिया गया है। बसों के जरिए अवैध ढुलाई का यह नेटवर्क अब कई राज्यों तक फैल चुका है।

कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा नेटवर्क

स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर कुछ बस संचालक खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लोगों ने परिवहन विभाग, जीएसटी विभाग और पुलिस प्रशासन से संयुक्त जांच अभियान चलाने की मांग की है ताकि अवैध ढुलाई और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके। क्षेत्र में चर्चा है कि यदि समय रहते इस नेटवर्क पर सख्ती नहीं की गई तो यात्री बसें पूरी तरह पार्सल परिवहन का माध्यम बन जाएंगी,जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

शराब के नशे में मासूम बच्चों के सामने डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या...

अधमरा होने पर पत्नी को कमर में बांधकर बाइक से पहुंचा अस्पताल,डॉक्टर ने किया मृत घोषित

मौत की जानकारी होते ही लाश को छोड़कर अस्पताल से भागा आरोपी पति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।।
मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिठ्ठीकला में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी पत्नी की बच्चों के सामने बेरहमी से पिटाई कर दी। डंडे और पत्थर से हमला करने से गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार भिठ्ठीकला निवासी 23 वर्षीय हीरा बाई का पति प्रदीप अगरिया गुरुवार दोपहर शराब पीकर घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच

विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते प्रदीप ने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। घर में मौजूद छोटे-छोटे बच्चे डरकर रोने लगे। सात वर्षीय बड़ी बेटी सिया अपनी मां को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डंडे और पत्थर से पत्नी पर लगातार हमला किया,जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच हालत बिगडऩे पर आरोपी पत्नी को कमर में गमछे से बांधकर बाइक से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां उसने डॉक्टरों को सडक़ दुर्घटना में घायल होने की जानकारी दी। जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर मिलते ही अस्पताल से भागा आरोपी : महिला की मौत की जानकारी मिलते ही आरोपी पति अस्पताल में शव छोड़कर फरार हो गया। रात करीब 11 बजे मृतका के मायके पक्ष को घटना की सूचना मिली। परिजन अस्पताल पहुंचे और शुक्रवार को मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की।

अक्सर करता था मारपीट

मृतिका के पिता ने बताया कि हीरा बाई ने करीब 15 वर्ष की उम्र में प्रदीप अगरिया से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया। मृतका के चार बच्चे हैं। इनमें तीन बच्चे उसके साथ रहते थे, जबकि एक बेटा ननिहाल में रहता है। मां की मौत और पिता के फरार होने से चारों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

नगर पालिक निगम अंबिकापुर में ऋण मेले का हुआ आयोजन

'मोर मकान मोर आस' के हितग्राहियों को ऋण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों एवं बैंकिंग संबंधी दी गई जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक 'मोर मकान मोर आस' अंतर्गत सुभाषनगर स्थित आवासों का आबंटन किया गया था। इस हेतु गुरुवार को ऋण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योजना अंतर्गत आवंटित 244 हितग्राहियों एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऋण मेला आयोजन का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों एवं बैंकों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा हितग्राही अंशदान की राशि जमा करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी प्रदान की गई। नगर पालिक निगम के अधिकारियों ने उपस्थित हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने प्रेरित किया तथा समय पर

आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की। बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान करते हुए ऋण स्वीकृति एवं अंशदान जमा प्रक्रिया संबंधी जानकारी दी गई। नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा आयोजित इस ऋण मेले से हितग्राहियों को आवास निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन को गति मिलेगी। कार्यक्रम में सहायक नोडल अधिकारी प्रेम प्रकाश दुबे, सीएलटीसी सोशल जगदम्बा त्रिवेदी, सीएलटीसी सिविल उत्कर्ष पांडे, लिपिक अलका पांडे, बैंक एवं हाउसिंग फाइनेंस के प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे।

मामूली विवाद में तलवार लेकर पहुंचे युवक महिला पर हमला,3 आरोपी गिरफ्तार....

सिर पर किया वार,कोतवाली पुलिस ने तलवार जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
शहर के नमनाकला इलाके में मामूली विवाद के दौरान तलवार लहराकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में महिला के सिर पर तलवार के हत्थे से वार किया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की तलवार भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार महामाया पेट्रोल पंप के पीछे खटिकपारा नमनाकला निवासी अंजनी सारथी ने थाना कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 मार्च 2026 को मोहल्ले का सूर्या सोनवानी उर्फ लेदरी अपने साथी गोपी और गोलू के साथ हाथ में तलवार लेकर उसके घर पहुंचा था। मामूली विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और तलवार के हत्थे से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसे चोट आई। प्रार्थिया की शिकायत पर थाना

कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 174/2025 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे।

मुखबिर की सूचना पर दबिश : नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के मार्गदर्शन में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सूर्या सोनवानी उर्फ लेदरी (19) निवासी झंझटपारा नमनाकला अंबिकापुर, गोपी चौधरी (27) निवासी नमनाकला खटिकपारा तथा रवि गुप्ता उर्फ गोलू (24) निवासी नमनाकला अंबिकापुर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

तलवार जब्त, भेजे गए जेल

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक नग लोहे की तलवार जब्त की है। इसके बाद विधिवत कार्रवाई करते हुए 14 मई 2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पूरे मामले की कार्रवाई में उप निरीक्षक के.के. यादव, प्रधान आरक्षक रजनीकांत मिश्रा, सियाराम मरावी, सतीश सिंह तथा आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा, लालभुवन सिंह और अमित विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

समलाया युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित,युवाओं में दिखा उत्साह

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में हुई घोषणा,संगठन को मजबूत करने युवा टीम को मिली जिम्मेदारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
स्थानीय सर्किट हाउस अंबिकापुर में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, मंत्री राजेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर एवं अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की सहमति, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निशांत सिंह तथा मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी की अनुशंसा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल समलाया की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समलाया मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष आयुष दुबे द्वारा मंडल की टीम का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नामों

पर मुहर लगाई गई। मंडल महामंत्री के रूप में इशू केसरवानी एवं सक्षम कश्यप को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि युवाओं की यह नई टीम पार्टी की रीति-नीति को जन-जन तक पहुँचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। आगामी कार्यक्रमों और जनहित के कार्यों में युवा मोर्चा अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। वरिष्ठ नेताओं ने विश्वास जताया कि युवाओं की नई टीम ऊर्जा और समर्पण के साथ संगठन को नई दिशा देगी। घोषणा के दौरान भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, महामंत्री द्वय अरुणा सिंह, उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी रूपेश दुबे, मन की बात प्रभारी जनमिजय मिश्रा सहित निलेश सिंह, मनोज अग्रवाल, अजय सोनी, अभिषेक सिंह देव, सर्वेश तिवारी, सुश्री प्रिया सिंह, दीक्षा अग्रवाल, विकास शुक्ला, शानू कश्यप, अंशुल श्रीवास्तव, रविकांत उरांव, अनीश सिंह, अविनाश मंडल, अभिषेक सिंह (पिंटी), रवजोत सिंह, अनुराग शुक्ला, सौरभ मिश्रा, अभिषेक माथुर, आदित्य पाण्डेय, शैलेन्द्र चौबे, प्रिंस तिवारी एवं युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में सरगुजा का दम,12 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक

कोरबा में आयोजित प्रतियोगिता में 14 बच्चों ने लिया हिस्सा, आनंदम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ सम्मान समारोह...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
कोरबा में आयोजित राज्य स्तरीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में सरगुजा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में सरगुजा से 14 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 12 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर बड़ी सफलता दर्ज की। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद आनंदम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित किकबॉक्सिंग क्लब में खिलाड़ियों के सम्मान में एक छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष

विंदेश्वर शरण सिंह देव,शैलेन्द्र प्रताप सिंह,अतुल मेहता एवं राघवेंद्र प्रताप सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान विंकी बाबा ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और आगामी नेशनल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सरगुजा के खिलाड़ी लगातार खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं।

राजीव भवन में फिर चोरी,कांग्रेस कार्यालय में तीसरी वारदात से मचा हड़कंप

घड़ी चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में चोरी और तोड़फोड़,करीब एक लाख के नुकसान का दावा,कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।
शहर के सबसे संवेदनशील और व्यस्त माने जाने वाले घड़ी चौक क्षेत्र स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने कार्यालय के भीतर घुसकर सामान पार करने के साथ जमकर तोड़फोड़ भी की।

घटना के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दो वर्षों के दौरान राजीव भवन में चोरी की यह तीसरी घटना है। लगातार हो रही वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि जहां यह घटना हुई, उसके बेहद करीब यातायात पुलिस चौकी, कलेक्टर कार्यालय,पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। इसके बावजूद चोरों द्वारा बार-बार कांग्रेस कार्यालय को निशाना बनाया जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित कार्यालय में लगातार चोरी की घटनाएं होना 'दिया तले अंधेरा' वाली स्थिति को दर्शाता है। उनका आरोप है कि यदि प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था चुस्त होती तो इतनी संवेदनशील जगह पर इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होतीं। जानकारी के अनुसार चोरों ने कार्यालय के कमरों में रखे सामान को अस्त-व्यस्त कर दिया।

वहीं कार्यालय के कॉमन वॉशरूम में लगे कई उपस्करणों को भी तोड़ दिया गया। तोड़फोड़ इतनी अधिक थी कि कार्यालय प्रबंधन ने करीब एक लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजीव भवन पहुंचे। मौके का निरीक्षण करने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने थाना कोतवाली अंबिकापुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि लगातार तीसरी बार हुई चोरी की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में स्थित राजनीतिक दल का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

जनकपुर में दिनदहाड़े 4 लाख की चोरी ने उड़ाए होश

स्टेट बैंक से कुछ कदम दूर कार का कांच फोड़कर रकम पार,आरोपी सीसीटीवी में कैद फिर भी पुलिस के हाथ खाली

पहले ही दिन इनाम की घोषणा से उठे सवाल,क्या आरोपियों के सामने पुलिस ने मान ली मजबूरी?

-रवि सिंह-

जनकपुर/एमसीबी,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के जनकपुर में दिनदहाड़े हुई बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जनकपुर से रकम निकालकर निकले एक व्यक्ति की कार का कांच तोड़कर बदमाश लाखों रुपये लेकर फरार हो गए,घटना इतनी तेजी और प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई कि आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगी, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना बैंक से महज कुछ दूरी पर हुई, आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो गए, पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली,लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस द्वारा घटना के तुरंत बाद आरोपियों पर इनाम घोषित किए जाने को लेकर जिलेभर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार,प्रार्थी ध्रुव यादव (निवासी खिरकी,थाना कोटाडोल) ने भारतीय स्टेट बैंक,शाखा जनकपुर से चेक के माध्यम से 4,25,000 रुपये निकाले थे। उन्होंने यह रकम अपनी कार की सामने वाली सीट पर रखी थी। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने कार के दरवाजे का कांच तोड़कर नकदी से भरा बैग पार कर दिया, इस घटना पर थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 98/2026, धारा 305 (ख) (ग) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिनदहाड़े हुई वारदात ने बढ़ाया डर का माहौल- जनकपुर जैसे अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में दिनदहाड़े इस तरह की बड़ी चोरी ने आम लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है,लोगों का कहना है कि जब बैंक क्षेत्र में,लोगों की आवाजाही के बीच और मुख्य इलाके में इस तरह की घटना हो सकती है तो फिर आम आदमी खुद को कहां सुरक्षित माने? स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था अक्सर कमजोर रहती है। कई बार संदिग्ध लोग बैंक परिसर के आसपास घूमते दिखाई देते हैं,लेकिन उन पर कोई निगरानी नहीं होती। अब इस घटना के बाद लोग बैंक से रकम निकालने में भी डर महसूस कर रहे हैं।

बैंक से निकाले थे लाखों रुपये, पहले से पीछा कर रहे थे आरोपी?

जानकारी के अनुसार प्रार्थी ध्रुव यादव निवासी खिरकी ने जनकपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जनकपुर से करीब 4,25,000 की रकम निकाली थी, रकम कार की सामने वाली सीट पर रखी गई थी, बताया जा रहा है कि बैंक से बाहर निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर कार खड़ी थी और इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से कार का कांच तोड़ा और रकम से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए, घटना के तरीके को देखकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि आरोपी बैंक से ही पीड़ित पर नजर बनाए हुए थे और रकम निकालने के बाद लगातार उसका पीछा कर रहे थे, जैसे ही मौका मिला, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

सीसीटीवी में आरोपी कैद,पहचान भी हुई,फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? पुलिस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विवेचना के दौरान आरोपियों की पहचान पिंटू यादव निवासी कटिहार बिहार तथा सुमित सिसोदिया उर्फ बंदर निवासी अनूपपुर मध्यप्रदेश के रूप में हुई है,पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन यही बात अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। जब आरोपी चिन्हित हैं,उनके नाम और पते पुलिस के पास हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं,तब आखिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? लोगों के बीच चर्चा है कि तकनीक के इस दौर में पुलिस मोबाइल लोकेशन,सीसीटीवी नेटवर्क,टोल प्लाजा फुटेज और साइबर ट्रैकिंग के जरिए कई मामलों का कुछ ही घंटों में खुलासा कर देती है,फिर इस मामले में पुलिस की कार्रवाई इतनी धीमी क्यों नजर आ रही है?

पहले ही दिन इनाम की घोषणा,लोगों ने उठाए सवाल

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक एमसीबी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 के इनाम की घोषणा की गई, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जो भी व्यक्ति आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने उल्टा कई सवाल खड़े कर दिए हैं,लोगों का कहना है कि आमतौर पर इनाम की घोषणा तब की जाती है जब आरोपी लंबे समय तक फरार हों या पुलिस को कोई सुराग न मिल रहा हो, यहां तो घटना के शुरुआती दौर में ही इनाम घोषित कर दिया गया, ऐसे में चर्चा यह भी है कि क्या पुलिस ने शुरुआत में ही यह मान लिया कि आरोपी उसकी पकड़ से बाहर हैं? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि पुलिस उसी तेजी से दबिश और तकनीकी जांच करती जिस तेजी से इनाम घोषित किया गया, तो शायद आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके होते।

साइबर सेल और तकनीकी जांच पर टिकी उम्मीदें...

अब इस पूरे मामले में लोगों की उम्मीदें साइबर सेल और तकनीकी टीम पर टिक गई हैं,जानकारों का कहना है कि यदि पुलिस गंभीरता से तकनीकी जांच करे तो आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए,बैंक के सीसीटीवी,आसपास लगे कैमरे, मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन के समय की गतिविधियां और संभावित भागने के रास्तों की डिजिटल निगरानी के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकती है, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की साइबर टीम और जांच एजेंसियां इस मामले को कितनी तेजी से सुलझा पाती हैं।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार को घेरा

घटना को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है,उन्होंने कहा कि जनकपुर में स्टेट बैंक से महज कुछ कदम दूरी पर दिनदहाड़े कार का कांच तोड़कर लाखों रुपये चोरी हो जाना बेहद चिंताजनक है,उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं,उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि बैंक क्षेत्र में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी कहां जाए?

अब पुलिस के सामने प्रतिष्ठा का सवाल

जनकपुर की इस हाईप्रोफाइल चोरी की घटना ने अब पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, एक तरफ आरोपी सीसीटीवी में कैद हैं,दूसरी तरफ पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं सकी है,ऐसे में यह मामला अब केवल चोरी का नहीं,बल्कि पुलिस की कार्यक्षमता और तकनीकी क्षमता की परीक्षा बन चुका है,जनता अब केवल प्रेस विज्ञप्ति और इनाम की घोषणा नहीं,बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी देखना चाहती है, अब देखना यह होगा कि एमसीबी पुलिस इस मामले का खुलासा कितनी जल्दी कर पाती है और दिनदहाड़े हुई इस बड़ी चोरी के पीछे का पूरा नेटवर्क कब सामने आता है।

राहुल गुप्ता की शिकायत पर खुली नल-जल योजना की पोल,मंत्रालय रायपुर से जांच के आदेश

पुटसुरा में अधूरा और गुणवत्ताहीन मिला कार्य,कई बसाहटों में अब तक नहीं पहुंचा पानी

-संवाददाता-

बलरामपुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिले के ग्राम पुटसुरा में संचालित नल-जल योजना में भारी अनियमितताओं और गुणवत्ताहीन निर्माण का मामला सामने आया है। ग्राम निवासी राहुल गुप्ता की शिकायत के बाद मामला अब मंत्रालय स्तर तक पहुंच गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय रायपुर ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच प्रतिवेदन तलब किया है। मंत्रालय से जारी पत्र क्रमांक GENCOR-35/1082/2026-PHE दिनांक 05 मई 2026 के माध्यम से मिशन संचालक जल जीवन मिशन एवं प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्राम पुटसुरा में नल-जल योजना के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार, शासकीय राशि के दुरुपयोग और तकनीकी अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में ग्राम पुटसुरा निवासी राहुल गुप्ता ने आरोप लगाया था कि मे. रविरंजन कुमार राजा द्वारा गांव में नल-जल योजना का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कार्य पूर्ण हुए बिना ही सरपंच को कार्यालय बुलाकर यह कहलवाया गया कि गांव के सभी क्षेत्रों में पानी पहुंच रहा है, जबकि हकीकत में अधिकांश बसाहटों में पानी चालू ही नहीं हुआ था।

जांच में मिली कई गंभीर खामियां : शिकायत के बाद सहायक अभियंता उपखंड बलरामपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में योजना के कार्यों में कई गंभीर खामियां सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार 120 किलोलीटर क्षमता की टंकी में सीपेज पाया गया। टंकी की कलर कोटिंग मानक अनुरूप नहीं मिली तथा साफ-सफाई और फिलिंग का कार्य अधूरा पाया गया। इसके अलावा बाउंड्रीवॉल की फेसिंग जाली में एंगल की ऊंचाई जाली से कम पाई गई। सेमरपारा में आंशिक रूप से पानी चालू मिला, जबकि अन्य बसाहटों में पानी सप्लाई शुरू नहीं हो सकी थी। महुआरीपारा में पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई थी। गांव की पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का मरम्मत कार्य भी नहीं कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कई स्थानों पर केवल स्टैंड पोस्ट बनाकर कार्य पूर्ण दिखाने का प्रयास किया गया, जबकि उनका निर्माण भी संतोषजनक नहीं था। कई घरों में एफएचटीसी टूटे मिले, वहीं कुछ घरों में एक से अधिक एफएचटीसी कनेक्शन पाए गए।

ठेकेदार को चेतावनी,अनुबंध निरस्तीकरण की बात : कार्यपालन अभियंता कार्यालय की ओर से संबंधित ठेकेदार को निर्देश जारी कर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने और अनुबंध की शर्तों के अनुसार योजना का हैंडओवर सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों और निर्देशों की अवहेलना की गई तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी।

शिकायत के बाद मचा हड़कंप : ग्रामवासी राहुल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने लगातार विभागीय अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक शिकायत कर मामले को उठाया। इसके बाद जांच टीम गठित हुई और योजना की वास्तविक स्थिति सामने आई। मामले के उजागर होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। ग्रामीणों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो करोड़ों रुपए की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। अब लोगों की नजर मंत्रालय की अंतिम जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

सरगुजा सांसद और कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ जनसमस्याओं का निराकरण

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने बिजली बिलों की जांच और श्रम पंजीयन में तेजी लाने का दिया निर्देश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सुशासन तिहार अंतर्गत जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मूरता क्लस्टर में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 16 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित मांग एवं शिकायतों के कुल 1405 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मांग के 1374 तथा शिकायत के 31 आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों में से 72 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष लंबित आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

सांसद श्री महाराज ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर आम जनता को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है तथा मांगों एवं शिकायतों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपनी समस्याओं को खुलकर प्रशासन के समक्ष रखने की अपील की, ताकि समय पर समस्याओं का समाधान एवं योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का आग्रह किया।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों जैसे फौती, सीमांकन एवं बंटवारा आदि मामलों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की बात कही, जिससे समस्याओं का त्वरित एवं सुगम निराकरण किया जा सके।

नाम सुधार सूचना

मैं विजय कुमार अग्रवाल आ. श्री राम निवास अग्रवाल आयु 44 वर्ष,पता- वार्ड नं0 38, अग्रसेन वार्ड, चंन्दगी राम हाईट्स, मयुरा होटल के पीछे, ग्राउंड फ्लोर 03, अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. । यह कि, मेरे पिता का वास्तविक नाम राम निवास अग्रवाल/Ram niwas Agrawal है, जो कि सही है। मेरे पिता के आधार कार्ड संख्या 9503 0979 5976 में उनका सही नाम अंकित है।

मेरे शैक्षणिक दस्तावोजों मे मेरे पिता का नाम राम निवास अग्रवाल/Ram niwas Agrawal अंकित है जो कि सत्य एवं सही है। मेरे आधार कार्ड संख्या 2971 1796 2865 में मेरे पिता का नाम अंग्रेजी में रामनिवास अग्रवाल/Ramniwas Agrawal अंकित हो गया है जिसमें डिसटेंस नही दिया गया है जिस वजह से वह गलत है। मेरे आधार कार्ड में अंकित मेरे पिता के गलत नाम Ramniwas Agrawal को सुधार करते हुए सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार राम निवास अग्रवाल / Ram niwas Agrawal को मेरे आधार कार्ड में अंकित किये जाने हेतु शासकीय गजट में प्रकाशित करवाने हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
विजय कुमार अग्रवाल

झारखंड की ओर मवेशियों को मारते-पीटते ले जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार

सनावल पुलिस की कार्रवाई,5 मवेशी बरामद कर आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

-संवाददाता-

बलरामपुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

थाना सनावल क्षेत्र में मवेशियों को मारते-पीटते हुए झारखंड की ओर ले जा रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 25/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1960 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी रामकुमार यादव पिता मंगरू यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कुशफर थाना सनावल ने पुलिस को मोबाइल के माध्यम से सूचना दी कि दो व्यक्ति 5 रास बछड़ा,गाय एवं बेल को दौड़ाते,हांकते और मारते-पीटते हुए झारखंड की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना सनावल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और 5 मवेशियों को बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मवेशियों को मंडरू टोला उत्तर प्रदेश से खरीदकर सहयोगी रिश्तेदार के साथ मंडरू टोला होते हुए कुशफर के रास्ते ग्राम खालाटोला थाना धुरकी, झारखंड ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी शेर मोहम्मद अंसारी पिता सहादत अंसारी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खालाटोला सेराजनगर थाना धुरकी जिला गढ़वा (झारखंड) तथा परमात्मा यादव पिता बैजनाथ यादव उम्र 45 वर्ष निवासी कुशफर थाना सनावल से पूछताछ की।

करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी का आरोप,अपर कलेक्टर पर जांच शुरू

बेनामी संपत्ति और नियम विरुद्ध नामांतरण की शिकायत पर प्रशासन सख्त,पांच सदस्यीय समिति गठित

-संवाददाता-

सूरजपुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में पदस्थ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डी.के. सोनी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने वर्तमान अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा के खिलाफ संयुक्त जांच टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जगन्नाथ वर्मा ने अपने पूर्व पदस्थापना कार्यकाल के दौरान सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए करोड़ों रुपये की जमीन के सौदों में अनियमितताएं कीं। शिकायत के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-43 स्थित ग्राम मदनपुर की पुनर्वास भूमि को प्रभाव का इस्तेमाल कर निजी लोगों के नाम दर्ज कराया गया और बाद में बेनामी तरीके से उसका हस्तांतरण किया गया। शिकायतकर्ता डी.के. सोनी का दावा है कि जमीन की वास्तविक कीमत करीब दो करोड़ रुपये थी,लेकिन दस्तावेजों में कम मूल्य दर्शाकर स्टांप शुल्क में भारी गड़बड़ी की गई। मामले में कई चरणों में नामांतरण और रजिस्ट्री होने की बात भी सामने आई है,जिससे पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पांच सदस्यीय जांच समिति गठित

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में जिला पंचायत सीईओ बिजेंद्र सिंह पाटले को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एसडीएम शिवानी जायसवाल, शिकायत शाखा प्रभारी सुनील अग्रवाल,भू-अभिलेख अधीक्षक भूपेंद्र कुमारी बंजारे और तहसीलदार सूर्यकांत साथ को सदस्य बनाया गया है। समिति को पूरे मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरे राज्यों में निवेश का भी आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी ने प्रदेश और दूसरे राज्यों में पेट्रोल पंप, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियों में निवेश किया है। शिकायतकर्ता ने जांच एजेंसी के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है। वहीं अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और वे इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब पूरे मामले में जांच समिति की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग रामानुजगंज

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक - 1575/ NIT-2/2026-2027/व.ले.लि. दिनांकः 09/05/2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः - 20/05/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि : - 26/05/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 28/05/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे से
निविदाकारों की श्रेणी :- ई-पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी ''द'' से ''अ'' तक
निविदा प्रपत्र की कीमत (रु. में) :- 750/-
कार्य की अवधि :- 03 माह वर्षा ऋतु सहित

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत) लाख में अमानत राशि (रू.में) बैंक साल्वेंसी (रू.में)
1	2	3
2 T0003	रामानुजगंज संभाग के अंतर्गत 60 मीटर से कम मध्यम पुल का सर्वेक्षण / बोरिंग कार्य (वर्ष 2025-26) - 1. चरचरी से बलंगी मार्ग, 2. मदनपुर से मढ़ना नाला में मझली आईन नाला, 3. केनापारा से भलुई झोर मार्ग, 4. गोवर्धनपुर सरहुल मार्ग एवं 5. अल्का मानपुर से बच्छ्राजकुवर मार्ग प्रथम आमंत्रण	7.16 5500.00 300000.00

निविदा शर्तें -
निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग रामानुजगंज

जी.नं.- 262700702/4

सुशासन का 'सूखा' उत्सव

कागजों में दौड़ रहा जल जीवन मिशन

ज़मीन पर बूंद-बूंद को तरसती जनता

वाह रे सुशासन! साल भर से रावतसरई में बोरिंग बनी 'शोपीस',गड्ढों के भरोसे बुझ रही पारा डोल की प्यास...

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,15 मई 2026 (घटती-घटना)। एक तरफ प्रदेश सरकार सुशासन तिहार मनाकर विकास के ढोल पीट रही है,दूसरी तरफ गांवों की हकीकत उन दावों को खुलेआम चुनौती देती नजर आ रही है,सरकारी मंचों पर योज नाओं की सफलता के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन गांवों में लोग आज भी पानी की एक-एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं, कहीं करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन की पाइपलाइन हवा उगल रही है, तो कहीं एक साल पहले किए गए बोर आज भी बिना हैंडपंप के सरकारी शोपीस बनकर खड़े हैं, सवाल यह है कि आखिर हर घर जल का सपना कागजों से निकलकर जमीन तक कब पहुंचेगा?

तकनीकी लापरवाही या भ्रष्टाचार? सवालों के घेरे में पूरी योजना...

जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कई गांवों में व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाइपलाइन बिछाते समय तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई? क्या टंकी की ऊंचाई और पानी के दबाव का सही आकलन नहीं किया गया? क्या घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ? या फिर पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ कागजों में योजनाएं पूरी दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि धरातल पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सुशासन तिहार बनाम जल संकट सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर

प्रदेशभर में सुशासन तिहार के नाम पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं,मंचों से विकास और जनकल्याण की बातें हो रही हैं,लेकिन कोरिया जिले के गांवों की तस्वीर इन दावों की चमक फीकी कर रही है,एक ओर सरकार उपलब्धियों का उत्सव मना रही है,दूसरी ओर ग्रामीण पानी के लिए गड्ढों में बर्तन रख रहे हैं,सवाल यह है कि क्या सरकारी तंत्र को सिर्फ आंकड़े पूरे करने से मतलब है? क्या योजनाओं का उद्देश्य केवल उद्घाटन और फोटो सेशन तक सीमित रह गया है? ग्रामीणों का कहना है कि यदि योजनाओं का लाभ जमीन तक नहीं पहुंच रहा,तो ऐसे उत्सव जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं।

पंच संघ ने दी चेतावनी...एक हफ्ते में काम नहीं हुआ...तो होगा घेराव...

पंच संघ अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर रावतसरई में हैंडपंप स्थापना का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो समस्त पंच विभागीय कार्यालय का घेराव करेंगे,उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण बाल्टी,घड़ा और पानी भरने के बर्तन लेकर कार्यालय पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, उनका कहना है कि अब केवल ज्ञापन और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण लंबे समय से परेशान हैं और प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा।

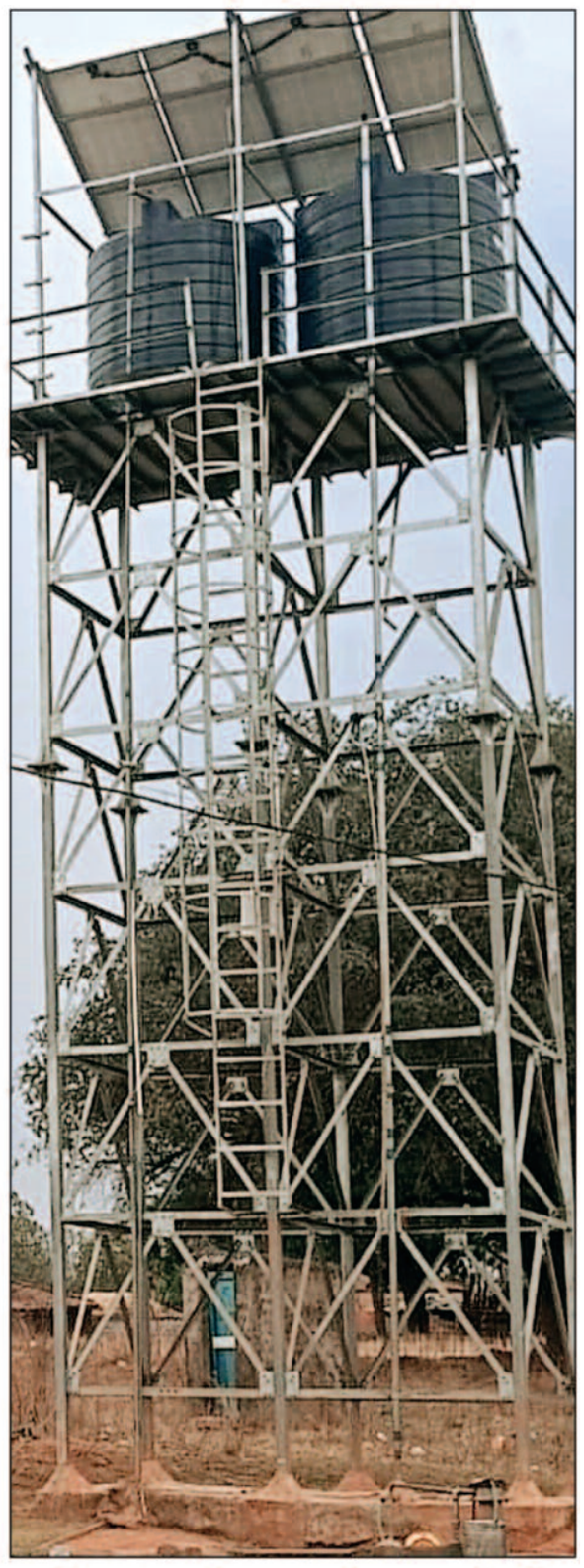

महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान...पानी की तलाश में रोजाना बढ़ रही मुश्किलें...

जल संकट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ रहा है,सुबह से लेकर देर शाम तक उन्हें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार दूर-दूर तक पानी ढूंढने जाना पड़ता है,ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सरकार योजनाओं की बात करती है,लेकिन असल समस्या समझने कोई नहीं आता। गड्ढों में जमा पानी भरना मजबूरी बन चुकी है,बच्चों की पढ़ाई,घर का काम और रोजमर्रा की जिंदगी सब पानी की कमी से प्रभावित हो रहे हैं।

जवाब मांग रही जनता...

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर करोड़ों की योजनाओं के बावजूद गांव प्यासे क्यों हैं? यदि बोरिंग होने के बाद हैंडपंप नहीं लगना है,यदि पाइपलाइन बिछने के बाद पानी नहीं आना है, तो फिर इन योजनाओं का फायदा किसे मिल रहा है? रावतसरई और पारा डोल की तस्वीरें केवल दो गांवों की कहानी नहीं हैं,बल्कि ग्रामीण विकास के उन दावों की हकीकत हैं जो कागजों पर चमकते हैं लेकिन जमीन पर दम तोड़ देते हैं,ग्रामीणों की मांग साफ है:— उन्हें भाषण नहीं,पानी चाहिए। उन्हें उत्सव नहीं,समाधान चाहिए।

रावतसरई में विकास का 'ड्राई मॉडल' साल भर पहले बोरिंग हुई,आज तक नहीं लगा हैंडपंप

रावतसरई ग्राम पंचायत के ग्राम सिंहपानी से जो तस्वीर सामने आई है,वह सरकारी कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, पंच संघ अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने आरोप लगाया कि पंच दिल कुँवर के घर के पास लगभग एक वर्ष पूर्व दो बोरिंग कराई गई थी,उस समय ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन विभाग की कार्यशैली ऐसी रही कि बोरिंग तो हो गई,मगर हैंडपंप आज तक नहीं लग पाया,अब हालात यह हैं कि गांव के बीचों-बीच खड़ी बोरिंग ग्रामीणों को पानी नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता की याद दिला रही है, वार्ड क्रमांक 8 की पंच दिल कुँवर का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की,दफ्तरों के चक्कर लगाए,लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। काम शुरू होने के बजाय फाइलें इधर-उधर घूमती रहीं,ग्रामीणों का कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं हो रही,तब आम जनता की परेशानी कौन सुनेगा?

जल जीवन मिशन की पाइपलाइन में हवा...पारा डोल में गड्ढों के भरोसे चल रही जिंदगी...

पारा डोल गांव में हर घर नल,हर घर जल का सपना पूरी तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है,कागजों में गांव को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, लेकिन जमीनी स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे योजना सिर्फ रिपोर्टों में सफल हुई हो,ग्रामीणों के अनुसार नलों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि पानी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता,मजबूरी में महिलाओं ने नलों के नीचे गहरे गड्ढे खोद लिए हैं,जहां बूंद-बूंद पानी जमा होता है और फिर उसी से बर्तन भरे जाते हैं, सुबह से शाम तक पानी भरने की जद्दोजहद में ग्रामीणों का आधा दिन निकल जा रहा है, कई महिलाओं ने बताया कि एक बाल्टी पानी भरने में घंटों लग जाते हैं,गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहले कुएं और हैंडपंप से कम से कम पानी मिल जाता था,लेकिन अब पाइपलाइन बिछने के बाद भी लोग प्यासे हैं। योजना आई जरूर,लेकिन पानी नहीं आया,यह बात अब ग्रामीणों की जुबान पर आम हो चुकी है।

CMYK

कोरिया कलेक्ट्रेट का स्थायी सिस्टम या प्रशासनिक चमत्कार?

दो दशक से जमे स्टेनो कलेक्टर पर उठे सवालों की लंबी फेहरिस्त

- स्टेनो टाइपिस्ट से कुछ महीनों में स्टेनोग्राफर, फिर प्रतिनियुक्ति की ऐसी कहानी कि बदलते रहे कलेक्टर...पर नहीं बदला प्रभार
- छः महीने में पदोन्नति, वर्षों की प्रतिनियुक्ति और प्रभाव का नेटवर्क चर्चा में
- कलेक्टर बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन नहीं बदला स्टेनो सिस्टम!
- प्रतिनियुक्ति या प्रशासनिक कब्जा? कोरिया कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी के प्रभाव की चर्चा तेज
- स्टेनो टाइपिस्ट से स्टेनोग्राफर तक का सफर बना सवाल, दस्तावेजों में नाम का अंतर भी चर्चा में...
- एसीबी में शिकायतें, निजी स्कूल को अनुदान और वर्षों का प्रभाव, सवालों के घेरे में कलेक्ट्रेट का चर्चित चेहरा
- कलेक्ट्रेट में फाइलों से ज्यादा प्रभाव की चर्चा, नई व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती
- दो दशक की प्रतिनियुक्ति का राज क्या है? कोरिया कलेक्ट्रेट में उठ रहे कई सवाल
- सिस्टम पर पकड़ या अनुभव का असर? प्रभावशाली स्टेनो को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल
- नई कलेक्टर के सामने चुनौती – क्या टूटेगा वर्षों पुराना प्रभाव का नेटवर्क?

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया, 15 मई 2026 (घटती-घटना)। सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि कुर्सियां बदलती रहती हैं,सिस्टम वही रहता है, लेकिन कोरिया कलेक्ट्रेट में यह कहावत अब कुछ ज्यादा ही सटीक मानी जा रही है,यहां वर्षों से पदस्थ एक प्रभावशाली स्टेनो कलेक्टर को लेकर जो चर्चाएं प्रशासनिक गलियारों में लंबे समय से दबे स्वर में होती थीं, वे अब खुलकर सामने आने लगी हैं।

मामला सिर्फ एक कर्मचारी के लंबे समय तक एक ही जगह टिके रहने का नहीं है, बल्कि सवाल नियुक्ति,पदोन्नति,प्रतिनियुक्ति, प्रशासनिक प्रभाव,निजी स्कूल,सांसद निधि और एसीबी तक पहुंची शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने तक जा पहुंचा है,सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां सामान्य कर्मचारी वर्षों तक एक पदोन्नति के लिए फाइलों के चक्कर काटते रह जाते हैं,वहीं यहां महज चार से छह महीने के भीतर स्टेनो टाइपिस्ट से स्टेनोग्राफर बनने की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है,और अब जब नई प्रशासनिक व्यवस्था जिले में आकार ले रही है, तब सवाल उठ रहा है– क्या यह सिर्फ एक कर्मचारी की कार्यकुशलता का मामला है, या फिर वर्षों में बना ऐसा प्रभावशाली तंत्र,जिसने पूरे सिस्टम को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया?

6 महीने में स्टेनो टाइपिस्ट से स्टेनोग्राफर! ये प्रशासनिक प्रतिभा या रिकॉर्ड का करिश्मा? दस्तावेजों ने खड़े किए सवाल

कोरिया कलेक्ट्रेट में वर्षों से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे चर्चित स्टेनो को लेकर अब जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार घनश्याम मिश्रा की नियुक्ति स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर 7 अप्रैल 1986 को हुई थी,लेकिन हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि महज कुछ ही महीनों बाद 27 अप्रैल 1986 को उन्हें स्टेनोग्राफर बना दिया गया,अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी पदोन्नति कैसे संभव हुई? सरकारी सेवा नियमों में जहां वर्षों तक कर्मचारी पदोन्नति की प्रतीक्षा करते रहते हैं,वहां कुछ महीनों में पद परिवर्तन होना अपने आप में जांच का विषय माना जा रहा है,जानकारों का कहना है कि यदि दस्तावेज सही हैं,तो पूरी प्रक्रिया की विभागीय जांच जरूरी हो सकती है,सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा अब व्यंग्य का विषय बन चुकी है,कई कर्मचारी मजाक में कहते नजर आते हैं कि यदि प्रतिभा इतनी तेज हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जरूरत ही क्या है, सबसे अधिक सवाल नाम को लेकर भी उठ रहे हैं,नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों में जहां पूरा नाम घनश्याम मिश्रा बताया जा रहा है,वहीं पदोन्नति संबंधी रिकॉर्ड में जेपी मिश्रा का उल्लेख होने की चर्चा है,अब लोग पूछ रहे हैं कि यह सिर्फ रिकॉर्ड की तकनीकी शैली है या फिर सरकारी फाइलों की वह पुरानी बीमारी, जिसमें नाम,पद और नियम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं?

पत्नी के नाम स्कूल और सांसद निधि का सवाल...

मामला केवल प्रशासनिक प्रभाव तक सीमित नहीं है,अब चर्चा परिवार द्वारा संचालित निजी स्कूल तक पहुंच चुकी है,स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि संबंधित कर्मचारी के परिवार से जुड़े निजी स्कूल को सांसद निधि से अनुदान प्राप्त हुआ,यहीं से बहस और तेज हो गई है,जानकारों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में निजी संस्थाओं को सीधे इस प्रकार की सहायता दिए जाने को लेकर नियम बेहद स्पष्ट होते हैं,ऐसे में यदि किसी निजी स्कूल को लाभ मिला है तो उसकी पात्रता,प्रक्रिया और स्वीकृति की जांच जरूरी हो जाती है,लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सामान्य निजी स्कूलों को भी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, या फिर प्रभाव और पहुंच का फर्क यहां भी दिखाई देता है?

सबसे बड़ा सवाल–आखिर सिस्टम चल कौन रहा है?

पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था नियमों से चल रही है या फिर कुछ प्रभावशाली लोगों की पकड़ से? क्या दो दशक से अधिक समय से चली आ रही प्रतिनियुक्ति की समीक्षा होगी? क्या पदोन्नति संबंधी दस्तावेजों की जांच होगी? क्या वेतन आहरण और विभागीय स्वीकृतियों का परीक्षण किया जाएगा? क्या निजी स्कूल और अनुदान से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है की क्या नई प्रशासनिक टीम इन मुद्दों पर कार्रवाई करने का साहस दिखाएगी? फिलहाल कोरिया कलेक्ट्रेट में चर्चा सिर्फ फाइलों की नहीं, बल्कि उस स्थायी सिस्टम की है,जिसने वर्षों में खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब लोग मजाक में कहने लगे हैं कलेक्टर बदलते रहते हैं लेकिन असली व्यवस्था वहीं रहती है।

मध्यप्रदेश शासन काल की नियुक्ति,लेकिन विभाग कौन-सा?

दस्तावेज यह भी बताते हैं कि उनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन काल में हुई थी,लेकिन यहां सबसे गंभीर सवाल विभागीय मूल पदस्थापना को लेकर उठ रहा है,जानकारी के अनुसार संबंधित कर्मचारी मूलतः मत्स्य निगम विभाग के कर्मचारी हैं,न कि राजस्व विभाग के,फिर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मत्स्य विभाग का कर्मचारी वर्षों से राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट में किस आधार पर पदस्थ है? क्या यह केवल प्रतिनियुक्ति है? यदि प्रतिनियुक्ति है तो उसकी समयसीमा क्या थी? और यदि समयसीमा समाप्त हो चुकी थी तो फिर निरंतर विस्तार किस आधार पर होता रहा? प्रशासनिक हलकों में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि यह मामला सामान्य प्रतिनियुक्ति से कहीं ज्यादा गहरा दिखाई देता है।

प्रतिनियुक्ति या स्थायी सरकारी पट्टा?

सरकारी व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, किसी विभाग का कर्मचारी कुछ समय के लिए दूसरे विभाग में सेवाएं देता है और फिर मूल विभाग में लौट जाता है,लेकिन कोरिया जिले में यह प्रक्रिया अब स्थायी प्रतिनियुक्ति मॉडल के रूप में चर्चा में है,बताया जाता है कि संबंधित कर्मचारी मूलतः मत्स्य विभाग से जुड़े हैं, लेकिन पिछले दो दशक से अधिक समय से राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट में ही पदस्थ हैं,यानी सरकारें बदलीं,अधिकारी बदलेज्कलेक्टर बदलेजजिले की सीमाएं तक बदल गईं,लेकिन यदि कुछ स्थायी रहा तो वह था यह प्रभावशाली प्रतिनियुक्ति,कर्मचारी अब तंज कसते हैं कि जिले में कुछ चीजें अस्थायी हो सकती हैं,सड़कें,योजनाएं,तबादले लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अमर होती हैं।

हर नए कलेक्टर के साथ नई शुरुआत...या पुराना नियंत्रण?

कलेक्ट्रेट के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जिले में चाहे कितने भी नए कलेक्टर आए हों,लेकिन कार्यालय का वास्तविक संचालन तंत्र हमेशा कुछ पुराने चेहरों के इर्द-गिर्द ही घूमता रहा,इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में यह प्रभावशाली स्टेनो भी बताए जाते हैं, कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों में उन्होंने ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया,जिसमें फाइलों की गति से लेकर अधिकारियों तक पहुंचने वाली जानकारी तक पर अप्रत्यक्ष प्रभाव बना लिया गया,हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच यह धारणा गहरी है कि कलेक्ट्रेट में कौन कब मिलेगा, कौन-सी फाइल पहले जाएगी और किसकी शिकायत किन कोनों में धूल खाएगी यह सब बिना अनुभव वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं,यही कारण है कि अब कई लोग उन्हें कर्मचारी कम और संस्था ज्यादा मानने लगे हैं।

कलेक्टर तक कौन पहुंचेगा...इसकी भी चर्चा!

प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी कम रोचक नहीं है कि कई बार अधिकारी और कर्मचारी खुद इस बात को लेकर असमंजस में रहते थे कि कलेक्टर से सीधे मिलें या पहले व्यवस्था से गुजरें,कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि वास्तविक शिकायतें कई बार ऊपर तक पूरी गंभीरता से पहुंच ही नहीं पाती थीं,वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अनुभवी कर्मचारी होने के कारण प्रशासनिक समन्वय में उनकी भूमिका स्वाभाविक थी,लेकिन सवाल यहीं खड़ा होता है, क्या किसी कर्मचारी की भूमिका इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि वह वर्षों तक प्रशासनिक संतुलन का अनौपचारिक केंद्र बन जाए?

एसीबी तक पहुंचीं शिकायतें...लेकिन कार्रवाई अब तक गायब!

मामले का सबसे दिलचस्प और गंभीर पक्ष यह बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ वर्षों में एसीबी तक सैकड़ों शिकायतें पहुंचीं, लेकिन अब तक किसी बड़ी विभागीय या कानूनी कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई, यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं,क्या शिकायतें केवल कागजों तक सीमित रहीं? क्या जांच शुरू हुई लेकिन पूरी नहीं हुई? या फिर सिस्टम ने हमेशा की तरह देखेंगे मोड में फाइलों को सुरक्षित रख दिया? कर्मचारियों के बीच अब यह व्यंग्य आम हो गया है कि सरकारी फाइलें दो जगह सबसे सुरक्षित रहती हैं रिकॉर्ड रूम में और जांच के नाम पर लंबित मामलों में।

स्कूल शिक्षा विभाग की चुप्पी भी सवालों में...

स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे निजी स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई बहुत तेजी से होती है,कभी मान्यता, कभी भवन,कभी रिकॉर्ड्ज किसी न किसी आधार पर नोटिस जारी हो जाते हैं,लेकिन जब मामला प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हो,तब कार्रवाई की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ जाती है? यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं,लोगों का कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है।

प्रशासनिक अनुभव या प्रभाव का साम्राज्य?

कुछ लोग संबंधित स्टेनो का बचाव भी करते नजर आते हैं, उनका कहना है कि वर्षों तक अलग-अलग अधिकारियों के साथ काम करने से स्वाभाविक रूप से अनुभव बढ़ता है और संपर्क भी बनते हैं,लेकिन विरोध करने वालों का तर्क अलग है,उनका कहना है कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का अत्यधिक प्रभाव स्वस्थ संकेत नहीं माना जाता,जब एक कर्मचारी व्यवस्था से बड़ा दिखाई देने लगे,तब सवाल केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगते हैं।

नई कलेक्टर के सामने सबसे बड़ी परीक्षा...

अब जिले में नई प्रशासनिक व्यवस्था बनने के बाद सबसे अधिक नजर इसी बात पर है कि क्या वर्षों से चली आ रही इस स्थायी व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई देगा? कई कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब प्रशासनिक पारदर्शिता और संतुलन को प्राथमिकता मिलेगी, वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वर्षों से मजबूत हो चुके नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकारी सिस्टम में फाइलें बदलना आसान होता है,लेकिन वर्षों से जमे प्रभाव को हटाना बेहद कठिन।

टैलेंट भी,विरासत भी...फिर कहां कमी! कैंप-पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा सारा अली खान का स्टारडम?

सारा अली खान,एक मजबूत फिल्मी विरासत के बावजूद,अपने करियर में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। फ्लॉप फिल्में सारा ने जरूर दीं,लेकिन क्या वाकई में सारा को रिस्क लेने से डर है? सिनेमा में जब कोई आता है तो उसके काम करने के अंदाज की तारीफ खूब होती है। अबतक सिनेमा में कई स्टार्स आए हैं, जिन्होंने अपने दम पर नाम बनाया, पहचान बनाई और वह सिनेमा छाए भी रहे। हालांकि स्टारडम के ढोल दूर के ही सुहावने लगते हैं, इसे पाना और फिर इसे संभालकर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है।

स्टारकिड्स के दौर में आज कई स्टार्स हैं जो सिनेमा को आगे बढ़ा रहे हैं,इन्हीं में से एक नाम आता है सारा अली खान का। वही सारा जिनका ताल्लुक फिल्मी परिवार से है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सारा थोड़ी अलग-थलग सी दिखाई पड़ी हैं,पर कैसे

सारा के करियर को लगी बुरी नजर?

सारा अली खान का करियर आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां टैलेंट और विरासत तो भरपूर है, लेकिन नंबर 1 की कुर्सी दूर होती जा रही है। एक शानदार फिल्मी खानदान सारा के पास है,लेकिन बावजूद इसका सारा का पिछड़ना बॉलीवुड के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। सारा अली खान का करियर ग्राफ किसी रोलर कोस्टर सवारी से कम नहीं रहा है।

2018 में केदारनाथ से जब उन्होंने डेब्यू किया, तो लगा कि बॉलीवुड को अगली बड़ी हीरोइन मिल गई है। स्टारकिड्स के दौर में सारा की एंट्री तब हुई जब नेपोटिज्म जैसा मुद्दा चरम पर था। हालांकि सारा ने खुद ने अपने अलग अंदाज, हाजिरजवाबी और सादगी ने दर्शकों का चहेता बनाया, लेकिन आज, 2026 में परिदृश्य अलग है।

फिल्मों के चुनाव में चूकीं सारा?

सारा के फिल्मी करियर पर अगर नजर डालेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि सारा ने कई फिल्में ऐसी कीं,जो कमाल की तो रहीं, लेकिन शायद सारा की प्लेसमेंट उन फिल्मों में सही नहीं बैठी। सारा ने शुरुआत बहुत मजबूत की थी, लेकिन केदारनाथ और सिम्बा के बाद उनकी फिल्म चॉइस ने फैंस को निराश किया।

इन फिल्मों के बाद सारा रीमेक का जाल में उलझ गईं। कुली नंबर 1 और लव आज कल 2 जैसी फिल्मों में सारा के अभिनय की काफी आलोचना हुई। इन फिल्मों के फ्लॉप होने से उनकी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। हालांकि ट्रोलिंग वाले दौर में सारा ने ये स्वीकार भी किया और वो फीडबैक लेने से पीछे नहीं हटीं।

उन्होंने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ीं। हालांकि उनकी पिछली कई फिल्में जैसे गैसलाइट,अतरंगी रे, ऐ वतन मेरे वतन सीधे ओटीटी पर रिलीज हुईं। ओटीटी पर फिल्में थोड़ी बहुत सफल तो रहीं, लेकिन जो लार्जर दैन लाइफ स्टारडम थिएटर से मिलता है, वह सारा के हाथ से फिसलता गया। कई फ्लॉप फिल्मों के चलते सारा के करियर में ब्रेक जरूर लगा।

कैंप,गैंग और पॉलिटिक्स से दूरी

सारा अली खान, जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे... ये तीन लगभग एक साथ ही लिए जाते हैं। इन तीनों ने ही सिनेमा में आगे-पीछे डेब्यू किया है। तीनों ने अलग-अलग फिल्में कीं। एक दौर था जब अनन्या पांडे जमकर ट्रोल की जाती थीं। अनन्या ट्रोलर्स का इस कदर शिकार हुईं कि उनकी हर चीज के लिए उन्हें ट्रोल किया गया।

इसी तरह जाह्नवी भी ट्रोलिंग से नहीं बच पाईं। हालांकि उस वक्त में सारा का गेम थोड़ा ऊपर जरूर था। सारा का सादगी भरा अंदाज,उनका लोगों से बातचीत करना। यहां तक कि सारा जब मीडिया से भी बात करती थीं तो बड़े अदब पेश आती थीं। हालांकि अभी वही है, लेकिन सारा बदले वक्त में शायद खुद को बदल नहीं पाईं और धीरे-धीरे सारा एक दायरे में सीमित रह गईं। अनन्या ने अपनी फिल्मों की च्वॉइस अच्छी रखी तो वहीं जाह्नवी के साथ भी कहीं ना कहीं यही रहा है।

हालांकि अनन्या की चर्चा ज्यादा इसलिए रहती है, क्योंकि अनन्या के काम को अब लोग पसंद करने लगे। अनन्या ने जेनजी ऑडिएंस को ध्यान में रखकर अपनी फिल्म का चुनाव किया है। दोनों एक्ट्रेसेस का बी-टाउन पार्टीज में एक्टिव रहना, लाइमलाइट में रहना शायद इनके लिए फायदेमंद रहा है। यहां तक कि करण जौहर के साथ भी अनन्या-जाह्नवी के रिश्ते ज्यादा अच्छे रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मेकर्स और स्टार्स के साथ दोनों का जुड़ाव ज्यादा नजर आया है।

बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो किसी बड़े कैंप का हिस्सा होना जरूरी है, लेकिन सारा ने अपने लिए एक स्वतंत्र राह चुनी। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े बजट की पॉपकॉर्न एंटरटेनर फिल्में और मेगा-प्रोजेक्ट्स सारा के बजाय उनके प्रतिद्वंद्वियों की झोली में ज्यादा गिरे।

सारा किसी एक कैंप की पोस्टर गर्ल बनकर नहीं रहीं, जिससे उन्हें मिलने वाले बड़े अवसरों में कमी आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि, दोनों ने सारा की तुलना में खुद को अधिक वर्सेटाइल और विजिबल रखा है।

लाइमलाइट से सारा की दूरी

सारा का कोरोनाकाल के बाद से वक्त बदलना शुरु हुआ है। अनन्या की तुलना में सारा को ज्यादा मजबूत माना गया, लेकिन वक्त बदला और आज तस्वीर कुछ और ही है। शुरुआत में सारा का नमस्ते और सारा की शायरी लोगों को बहुत पसंद आया। सारा की सबसे बड़ी यूएसपी उनकी सादगी रही है।

हालांकि सारा ने लाइमलाइट से खुद को दूर रखा है। सारा वक्त-वक्त पर बाकी स्टार्स की तरह ज्यादा मीडिया में नहीं रहती हैं। एक वक्त था जब वो मीडिया से ज्यादा बातचीत करती थीं। हालांकि अब सारा मीडिया से भी कम ही मुखातिब होती हैं। इंड्स्ट्री में आज खुद का पीआर हर स्टार करता है, लेकिन शायद सारा ने अपनी पीआर स्ट्रैटजी पर भी ध्यान देना बंद सा कर दिया। हां, शायद ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि अक्सर किसी स्टार की स्टारवैल्यू में पीआर स्ट्रैटजी का बहुत बड़ा हाथ होता है।

क्या सही फिल्में नहीं चुन रहीं सारा?

बाकी स्टारकिड्स की तुलना में सारा के पास फिल्में तो हैं, लेकिन शायद वह फिल्मों में रिस्क लेने से डर रही हैं। सारा को उनकी एक्टिंग के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि कुछ फिल्मों में उनकी एक्टिंग बेहतरीन रही है। विक्की कौशल के साथ जरा हटके जरा बचके, धनुष के साथ अतरंगी रे और ओटीटी की फिल्मों में सारा के काम की सराहना हुई है। हालांकि सारा बड़े बैनर्स की फिल्मों तक सारा नहीं पहुंच पा रही हैं, पर सारा खुद मानती हैं कि ओवरनाइट मिलने वाली सक्सेस अक्सर ज्यादा दिन तक नहीं रुकती।

एक इंटरव्यू में सारा ने बताया कि जब वो इंड्स्ट्री में आईं तो उनकी मां अमृता सिंह ने उन्हें सलाह दी थी कि, जो सक्सेस रातोंरात मिल जाए वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। शायद सारा यही मानती हैं, लेकिन सारा शायद रिस्क लेने से बच रही हैं, जो उनके करियर के लिए घातक हो सकता है।

फिल्मी परिवार से है सारा का ताल्लुक

सारा अली खान एक बड़े फिल्मी परिवार से आती हैं। सारा की दादी मां शर्मिला टैगोर अपने जमाने की बड़ी अभिनेत्री रही हैं। पिता सैफ अली खान हैं, जो खुद एक बड़े स्टार हैं। मां अमृता सिंह भी टॉप एक्ट्रेस रहीं, तो वहीं करीना कपूर खान भी सुपरस्टार हैं और करीना के साथ भी सारा के रिश्ते अच्छे रहे हैं।

हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मी परिवार से होना सारा के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं लाया है। सारा को परिवार का सपोर्ट है,लेकिन अपने दम पर सब करना चाहती हैं। करीना के साथ करण की दोस्ती बेहद गहरी है, लेकिन करण की किसी बड़ी पार्टी का हिस्सा सारा कम ही होती हैं।

एक दौर था जब आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा की तुलना की जाती थी। उस दौर में कहा गया कि परिणीति आलिया से बड़ी एक्ट्रेस बनने के काबिल हैं, जबकि आलिया उस वक्त में जमकर ट्रोल होती थीं। हालांकि आलिया ने आत्मविश्वास रखा और खूब मेहनत की। आज आलिया और परिणीति के करियर के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारा के करियर में यही है, शायद सारा को खुद में आत्मविश्वास रखना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और खुद पर ज्यादा मेहनत करनी होगी

। वहीं सारा की यूं तो किसी से इंड्स्ट्री में दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर अक्सर वायरल होने वाले औरी सारा पर खूब कटाक्ष करते हैं। सारा और औरी के बीच का विवाद भी कई बार बाहर आया। औरी अनन्या और जाह्नवी के अच्छे दोस्त हैं, जबकि सारा को वह अपना दोस्त नहीं मानते हैं।

सारा अली खान ने अब लंबे वक्त बाद पति पत्नी और वो दो से बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म में सारा के साथ आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी हैं। इस फिल्म में सारा के पास भी ज्यादा कुछ करने को नहीं नजर आया है। हालांकि सारा को जितना स्क्रीन मिला, वो उतना अच्छा करके गईं।

अब ये फिल्म उनके लिए मेक या ब्रेक वाली स्थिति हो सकती है। सारा के पास जुनून और क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन वो रणनीति के मामले में पीछे रह गईं। उम्मीद है सारा अपनी मां अमृता और दादी शर्मिला टैगोर की तरह पर्दे पर नये आयाम तो स्थापित जरूर करेंगी।

35 साल पुराना कल्ट सांग अमिताभ बच्चन को लगा अश्लील,हुक स्टेप करने में छूटे पसीने

अमिताभ बच्चन के तीन दशक पुराने एक आइटम नंबर ने तहलका मचा दिया था। हालांकि, इस गाने को शूट करने में वह बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन न केवल अभिनय, बल्कि अपने डांस को लेकर भी खूब धमाल मचाया है। अभिनेता ने कई कल्ट गाने दिए लेकिन एक गाने को शूट करने में उनके पसीने छूट गए थे। 35 साल पुराना अमिताभ बच्चन का एक गाना आज भी बहुत पॉपुलर है। सिर्फ लिरिक्स, म्यूजिक और आवाज ही नहीं,गाने में डांस भी महफिल में चार-चांद लगा देता है। अमिताभ ने अपने डांस नंबर से तहलका मचा दिया था।

हालांकि,अभिनेता को गाने का हुक स्टेप अश्लील लगा था।

अमिताभ बच्चन को अश्लील लगा गाना

जी हां, अमिताभ बच्चन गाने की शूटिंग के दौरान बहुत झिझक रहे थे। वह हुक स्टेप भी नहीं कर रहे थे। फिर उनकी पत्नी जया बच्चन ने उनकी ये झिझक या यूं कहें कि मन बदला। जिसे वह अश्लील मान रहे थे, जया को वह डांस बहुत पसंद आया।जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो है हम फिल्म का आइटम सॉन्ग जुम्मा चुम्मा दे दे। इस गाने में अमिताभ बच्चन ने बोल्ड हसीना किमी केतकर के साथ डांस किया था। कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले का ये गाना कल्ट क्लासिक बन गया है। मगर अभिनेता इस गाने को लेकर खास श्योर नहीं थे।

शूटिंग करने में झिझक रहे थे अमिताभ

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने एक बार बताया था कि बिग बी गाने की शूटिंग के दौरान बहुत अनकंफर्टेबल थे, लेकिन जब जया बच्चन ने उनका रिहर्सल देखा तो इसे आइकॉनिक बता दिया और ताली बजाने लगीं। उनका अमिताभ की तारीफ करना, बिग बी का मन बदलने के लिए काफी था। बाद में अभिनेता ने अच्छे से गाने की शूटिंग की और आज यह कल्ट क्लासिक बन गया।

इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, जबकि म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह गाना, फिल्म से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ था।

वेलकम टू द जंगल' का टीज़र आउट

वेलकम टू द जंगल के मेकर्स ने फिल्म का बहुत इंतज़ार किया जा रहा ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ कर दिया है, जिसमें मेटा-ह्यूमर, नॉस्टैल्जिया और स्लैपस्टिक तमाशे पर बनी एक बड़े पैमाने की,अफरा-तफरी वाली कॉमेडी की पहली झलक दिखाई गई है। अहमद खान के डायरेक्शन और फिरोज ए. नाडियाडवाला के प्रोड्यूस की हुई यह फिल्म 26 जून, 2026 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। वेलकम बैक के बाद, पॉपुलर वेलकम फ्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त के तौर पर, यह टीज़र एक सेल्फ-अवेयर कॉमेडी टोन पेश करता है जो ज़्यादातर पैरोडी और ग्रुप से चलने वाली अफरा-तफरी पर आधारित है। टीज़र स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डिस्क्लेमर पर एक सटायरिकल ट्विस्ट के साथ शुरू होता है,जो तुरंत एक मज़ेदार टोन सेट करता है। ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट में लिखा है इस फिल्म को बनाने में किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया...सिवाय कुछ घोड़ों और हम गधों के। इसके बाद फुटेज एक फिक्शनल फिल्म-सेट की कहानी में बदल जाती है, जहाँ पूरी कास्ट ऐसे किरदार निभाती है जो प्रोडक्शन के माहौल में फंसे होते हैं और जिन्हें परफॉर्म करने के लिए करोड़ों रुपये मिलते हैं। टीज़र में तेज़-तर्रार डायलॉग और सिचुएशनल ह्यूमर है। एक खास पल में, अक्षय कुमार का किरदार अस्त-व्यस्त प्रोडक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करता है,लेकिन फिर यह कहते हुए लौटता है कि पैसा हमेशा बीच में आ जाता है। एक्शन जल्दी ही बढ़ा-चढ़ाकर की गई गोलियों और ज़बरदस्त कॉमेडी सीक्वेंस में बदल जाता है। टीज़र एक स्टाइलिश टैगलाइन के साथ खत्म होता है जो इसके अस्त-व्यस्त टोन को और मज़बूत करता है, फेक फिल्म। रियल जंगल। रियल डेंजर।

खेल समाचार

साइमन हेल्मोट बने गल्फ जायंट्स के हेड कोच

अहमदाबाद,15 मई 2026। अडानी स्पोर्ट्सलाइन ने डीपी वर्ल्ड यूएई आईएलटी 20 के आने वाले सीज़न से पहले,अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्ट्रैटेजिस्ट साइमन हेल्मोट को गल्फ जायंट्स का हेड कोच बनाने की घोषणा की। हेल्मोट के पास घरेलू, इंटरनेशनल और फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट में दो दशकों से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें दुनिया की कुछ बड़ी टी 20 लीग में काम करना भी शामिल है। वह 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद टीम से जुड़े हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन और यूएई में बड़े टी 20 टूर्नामेंट में कई टाइटल जीतने वाले कैंपेन में योगदान दिया है। पिछले कुछ सालों में,उन्होंने हाई-परफॉर्मेंस टीम माहौल बनाने और दबाव वाली स्थितियों में खिलाड़ियों की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक मज़बूत नाम कमाया है। इस अपॉइंटमेंट से पहले, मिस्टर हेल्मोट ने मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ पांच सीज़न का समय पूरा किया,और टीम को 2024 में अपना पहला विमेंस बिग बैश लीग टाइटल जिताया। गल्फ जायंट्स के साथ अपनी ऑनबोर्डिंग के हिस्से के तौर पर, मिस्टर हेल्मोट ने हाल ही में अहमदाबाद में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर,मिस्टर प्रणव अडानी से मुलाकात की,ताकि गल्फ जायंट्स के लॉन्ग-टर्म विजन और आने वाले आईएलटी 20 सीज़न के लिए फ्रैंचाइजी की तैयारियों पर चर्चा की जा सके।

कीरोन पोलार्ड पर कार्रवाई,कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन पर लगा जुर्माना

मुंबई ,15 मई 2026। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड पर गवर्निंग बॉडी ने कार्रवाई की है। गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया है। द्वारा की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर पोलार्ड को मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। यह कार्रवाई मैच अधिकारियों के प्रति अनुचित व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के चलते की गई है। यह घटना मैच की दूसरी पारी के 19 वें ओवर के दौरान हुई,जब मैदान पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पोलार्ड ने चौथे अंपायर को लेकर आपत्तिजनक और अनुचित भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद मैच रेफरी ने मामले को गंभीरता से लिया। आईपीएल के आचार संहिता के आर्टिकल 2.3 के तहत यह उल्लंघन दर्ज किया गया है, जिसमें मैच के दौरान किसी भी अधिकारी के प्रति अपमानजनक भाषा या व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। लेवल-1 उल्लंघन के मामलों में आमतौर पर मैच फीस का जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट शामिल होते हैं।

आरसीबी में इंग्लिश गेंदबाज की एंट्री

सीएसके ने भी किया खलील अहमद की रिप्लेसमेंट का ऐलान,आईपीएल 2026 में तेज गेंदबाज कुलदीप यादव और रिचर्ड ग्लीसन की एंट्री हुई है...कुलदीप यादव ने सीएसके में चोटिल खलील अहमद को रिप्लेस किया है जबकि रिचर्ड ग्लीसन ने नुवान तुषारा की जगह ली है...

नई दिल्ली,15 मई 2026। आईपीएल 2026 में बचे हुए मैचों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंजर्ड बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद की जगह एक दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलदीप यादव को साइन किया है। वहीं, आरसीबी ने नुवान तुषारा की जगह रिचर्ड ग्लीसन को शामिल किया है।आईपीएल की तरफ से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया, कुलदीप यादव 30 लाख रुपये में सीएसके में शामिल होंगे, जबकि रिचर्ड ग्लीसन 1.6 करोड़ रुपये में आरसीबी का हिस्सा बनेंगे।

कुलदीप ने आरआर के लिए किया था डेब्यू

सीएसके में शामिल किए गए कुलदीप ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था। वह आरआर के लिए साल 2023 में भी खेले थे। दो सीजन के दौरान खेले 3 मैचों में उन्होंने 2 विकेट लिए थे।

रिचर्ड ग्लीसन का करियर

रिचर्ड ग्लीसन ने इंग्लैंड की तरफ से 6 टी20 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। उन्होंने लीग के 2024 और 2025 संस्करण में सीएसके और मुंबई इंडियंस (एमआई) का प्रतिनिधित्व किया था। ग्लीसन ने सीएसके के लिए 2 और एमआई के लिए 1 मैच खेला है। ग्लीसन के नाम आईपीएल में 2 विकेट हैं।

खलील अहमद हो गए थे चोटिल

खलील अहमद आईपीएल 2026 में सीएसके की तेज गेंदबाजी का प्रमुख चेहरा थे। वह 5 मैच खेले जिसमें उन्हें 2 विकेट मिले थे। इंजरी की वजह से उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा। खलील के दाहिने क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी। ऑपरेशन के बाद वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

नुवान तुषारा क्यों इस सीजन नहीं खेल पाए?

नुवाना तुषारा आरसीबी के लिए सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए। तुषारा श्रीलंका क्रिकेट के जरूरी फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद बाहर हो गए। जरूरी फिटनेस स्टैंडर्ड पूरे न कर पाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट ने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया था। आरसीबी 12 मैचों से 16 अंक लेकर अंकतालिका में पहले स्थान पर है, जबकि सीएसके 11 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

रॉबिन सिंह ने 15 साल के सफर के बाद मुंबई इंडियंस से किया विदाई

नई दिल्ली,15 मई 2026। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के साथ अपना लंबा रिश्ता ऑफिशियली खत्म कर दिया है, जिससे 2010 में शुरू हुआ उनका सफर खत्म हो गया है। रॉबिन ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह घोषणा की, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि उन्होंने न केवल आईपीएल टीम बल्कि आईएलटी 20 फ्रेंचाइजी एमआई एमिरेट्स से भी नाता तोड़ लिया है।

उन्होंने साफ किया कि हालांकि वह 2022 से मुंबई इंडियंस के आईपीएल सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा नहीं थे,लेकिन इस साल उनके विदेशी सेटअप के साथ भी उनका रोल खत्म हो गया। रॉबिन ने एक्स पर शेयर किया, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने ऑफिशियली मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ लिया है। हालांकि मैं 2022 से उनके आईपीएल स्टाफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस साल से एमिरेट्स लीग में उनकी टीम के साथ भी हूं। भारत के पूर्व क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी और उसके सपोर्टर्स को इतने सालों तक उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने आगे कहा, 2010 से मेरे इस शानदार सफर में सपोर्ट के लिए पूरे एमआई परिवार और फैंस का धन्यवाद। फ्रेंचाइजी को आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं।

योनेक्स सनराईज इंडिया ने बेंगलुरु में अपनी राष्ट्रव्यापी वर्कशॉप श्रृंखला का किया समापन

बेंगलुरु,15 मई 2026। योनेक्स सनराईज इंडिया ने शुक्रवार को गोल्डफिंच होटल में बेंगलुरु एडिशन के साथ अपनी देशव्यापी योनेक्स स्ट्रिंगिंग वर्कशॉप सीरीज को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके साथ ही, कंपनी ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से भारत के रैकेट खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को और पुख्ता किया है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस वर्कशॉप में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के 140 से अधिक स्ट्रिंगिंग पेशेवरों ने हिस्सा लिया। यह दक्षिण भारत में रैकेट स्ट्रिंगर्स के लिए आयोजित सबसे बड़े तकनीकी जमावड़ों में से एक था। इन सत्रों का नेतृत्व एक बार फिर योनेक्स स्ट्रिंग टीम के हेड स्ट्रिंगर और सुपरवाईजर टीम विल्स ने किया। उन्होंने उन्नत स्ट्रिंगिंग तकनीकों,मशीन कैलिब्रेशन,एथलीट-विशिष्ट सर्विसिंग आवश्यकताओं और शीर्ष स्तरीय बैडमिंटन व टेनिस टूर्नामेंटों में अपनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों पर केंद्रित विस्तृत व्यावहारिक प्रदर्शन किए।

23 साल बाद भी जिंदा है पीएससी-2003 घोटाले की आग
ये 'महाविद्रोह' सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा निर्णायक!

न पद चाहिए...न पैसा...केवल न्याय चाहिए...वर्षा डोंगरे की दो दशक पुरानी लड़ाई फिर सुर्खियों में...

- पीएससी-2003 : टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार का मामला,अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में!
- सिस्टम बिक सकता है,संघर्ष नहीं-पीएससी घोटाले के खिलाफ वर्षा डोंगरे फिर मुखर
- 23 साल पुराना घोटाला,लेकिन जख्म आज भी ताजा...न्याय की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर
- लोक अदालत में समझौते की चर्चा से भड़की बहस,पीएससी-2003 मामला फिर बना सुर्खियां

IAS-IPS अवॉर्ड हुए लोग खुश होंगे,लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं : पीएससी याचिकाकर्ताओं का बड़ा बयान

भ्रष्टाचार बनाम संविधान के बिच पीएससी-2003 के खिलाफ दो दशक से जारी कानूनी जंग

'ऑफर ठुकराया,समझौता नहीं किया' वर्षा डोंगरे ने फिर दोहराया संघर्ष का संकल्प

छत्तीसगढ़ पीएससी-2003 : हाईकोर्ट ने कहा था 'टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार',अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

23 साल पुराना घोटाला,'टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार' की लड़ाई और सिस्टम से टकराने वाली एक जिद का नाम – वर्षा डोंगरे

'न पद चाहिए,न पैसा... सिर्फ न्याय चाहिए',सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लड़ाई ने फिर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था

-न्यूज डेस्क-

रायपुर/बिलासपुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा-2003... यह सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नाम नहीं रह गया है,यह अब छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास का ऐसा अध्याय बन चुका है,जिसे हर नई पीढ़ी अलग-अलग तरीके से सुनती है,कोई इसे 'भर्ती घोटाला'कहता है,कोई'सिस्टम की सड़ांध ',तो कोई इसे उन युवाओं की अधूरी कहानी मानता है,जिनके सपनों को कथित भ्रष्टाचार ने निगल लिया,करीब 23 साल गुजर चुके हैं। कई चयनित अधिकारी अब बड़े पदों तक पहुंच चुके हैं,कुछ को प्रमोशन मिला,कुछ को आईएएस-आईपीएस अवॉर्ड मिला, कई सेवानिवृत्ति के करीब हैं,लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं,जिन्होंने इस लड़ाई को अभी खत्म नहीं माना,इन्हीं नामों में सबसे चर्चित नाम है वर्षा डोंगरे,वर्षा डोंगरे अब केवल एक याचिकाकर्ता नहीं रहीं,वे इस लंबे संघर्ष का चेहरा बन चुकी हैं,सिस्टम से लड़ने वाली वह महिला,जिसने कथित तौर पर समझौते के प्रस्ताव ठुकराए,अदालतों में खुद पैरवी की और अब भी कह रही हैं अंतिम फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा।

23 साल बाद भी क्यों जिंदा है यह मामला?

सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस भर्ती प्रक्रिया में कि दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ? क्यों आज भी लोग'पीएससी-2003' का नाम सुनते ही व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं? दरअसल यह मामला केवल चयन या अचयन का नहीं था, आरोप यह था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई, योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए और कथित रूप से अपात्र लोगों को चयनित कर लिया गया, यानी युवाओं के सपनों का चयन मेरिट से नहीं,बल्कि 'मैनेजमेंट' से हुआ ऐसा आरोप वर्षों से लगता रहा,और यही कारण है कि यह मामला धीरे-धीरे अदालत से निकलकर जनता की अदालत तक पहुंच गया।

'टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार'—एक टिप्पणी जिसने सिस्टम हिला दिया

वर्ष 2016 में जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया,तब एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में आया–'टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार।'यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल था,जिस पर राज्य की प्रशासनिक रीढ़ खड़ी होती है,लोक सेवा आयोग...यानी वह संस्था,जहां से भविष्य के अफसर निकलते हैं,जहां से प्रशासनिक ईमानदारी और शासन व्यवस्था की नींव तैयार होती है,लेकिन जब उसी संस्था पर अदालत इतनी तल्ख टिप्पणी करे,तो सवाल केवल परीक्षा पर नहीं,पूरे सिस्टम पर खड़े हो जाते हैं, यही वजह थी कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी।

जब वकील छूटे,तब याचिकाकर्ता खुद बन गए पैरवीकार

इस मामले की सबसे दिलचस्प और भावनात्मक कहानी यह है कि वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ते-लड़ते याचिकाकर्ताओं की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई,बताया जाता है कि शुरू में वकील केस लड़ रहे थे,लेकिन बाद में आर्थिक परेशानियों और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण कई बार ऐसा दौर आया जब याचिकाकर्ताओं को खुद अदालत में खड़ा होना पड़ा, कल्पना कीजिए...सामने बड़े-बड़े वरिष्ठ वकील, सरकारी पक्ष,कानूनी दांव-पेंच और दूसरी तरफ वे लोग,जिन्होंने कानून की पढ़ाई तक नहीं की,लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रही, यह वही दौर था जब सिस्टम ने शायद सोचा होगा कि'समय के साथ लोग थक जाएंगे।' कुछ थके भी, कुछ समझौते के लिए तैयार भी हुए, लेकिन कुछ लोग डटे रहे।

वर्षा डोंगरे ये वो नाम है जो सिस्टम से न डरने वाली 'उलगुलान' की आवाज

वर्षा डोंगरे का नाम अब इस पूरे संघर्ष की पहचान बन चुका है,वह आज भले डिप्टी जेलर हों,लेकिन उनके समर्थकों के लिए वह 'सिस्टम से लड़ने वाली महिला' हैं,उनका दावा है कि कोर्ट के बाहर भी कई बार'सेटलमेंट' के प्रयास हुए,समझाने,दबाव बनाने, मनाने और यहां तक कि'ऑफर' देने की बातें भी सामने आई, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया,अब यह दावा कितना सही है और कितना नहीं,यह अलग जांच का विषय हो सकता है,लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह बात बार-बार कही है कि उन्हें पद नहीं,न्याय चाहिए, और यही लाइन अब उनके समर्थकों के बीच नारा बन चुकी है।

एएसपी बन जाइए,मामला खत्म कीजिए,और फिर भी नहीं मानीं?

मामले का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि हाईकोर्ट के फैसले में उल्लेखित कथित प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की ओर से उन्हें 'ASP with Notional Promotion' और 11 साल का वेतन देने का ऑफर दिया गया था, यदि यह दावा सही है, तो सवाल और गंभीर हो जाते हैं,क्या सिस्टम इतनी बड़ी कीमत देकर मामला शांत करना चाहता था? क्या यह समझौता था या'डैमेज कंट्रोल '? लेकिन वर्षा डोंगरे का दावा है कि उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, यहीं से यह लड़ाई केवल नौकरी की नहीं, बल्कि 'स्वाभिमान' की लड़ाई बन गई।

सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत-समय

सरकारी मामलों में अक्सर कहा जाता है कि सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत'समय' होता है, समय बीतता जाता है...लोग बूढ़े हो जाते हैं... जिम्मेदार लोग रिटायर हो जाते हैं...फाइलें धूल खा जाती हैं...और धीरे-धीरे मामला इतिहास बन जाता है,शायद यही उम्मीद इस मामले में भी रही होगी,लेकिन पीएससी-2003 का मामला खत्म नहीं हुआ,बल्कि हर कुछ वर्षों में फिर जिंदा हो जाता है,क्योंकि यह केवल कोर्ट का केस नहीं है,यह उन हजारों युवाओं की भावना से जुड़ा मामला है,जो मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ।

भाजपा सरकार में भर्ती,कांग्रेस सरकार में प्रमोशन-राजनीति भी घेरे में...

वर्षा डोंगरे ने अपने बयान में एक और गंभीर राजनीतिक आरोप लगाया था उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार हुआ और बाद में कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हीं चयनित अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस-आईपीएस अवॉर्ड दिया गया,यानी उनके अनुसार सत्ता बदली,लेकिन सिस्टम नहीं बदला, हालांकि यह उनके व्यक्तिगत आरोप हैं और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक दल वास्तव में अलग-अलग होते हैं, या फिर सत्ता बदलने के बाद भी व्यवस्था वही रहती है?

लोक अदालत में सुलह? सबसे बड़ा विवाद यही

अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब लोक अदालत में सुलह की संभावना की चर्चा सामने आई,यहीं से विवाद और गहरा गया, लोग पूछ रहे हैं क्या'टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार'जैसे मामले में समझौता संभव है? क्या न्याय की लड़ाई का अंत पैसों या पदों से हो सकता है? वर्षा डोंगरे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है,उन्होंने साफ कहा कि यह मामला लोक अदालत में सुलह योग्य नहीं है,उनके अनुसार यह लड़ाई व्यक्तिगत लाभ की नहीं,बल्कि व्यवस्था में सुधार की है।

सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजरें...

अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, करीब 10 वर्षों से मामला वहां विचाराधीन है और अब सभी की नजरें अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा फैसला देता है,तो इसका असर केवल एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा,यह भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं,लोक सेवा आयोगों की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

सबसे बड़ा सवाल...क्या न्याय देर से मिलेगा या कभी नहीं?

23 साल...यह कोई छोटा समय नहीं होता, एक पूरी पीढ़ी इस दौरान जवान से अधेड़ हो जाती है, लेकिन पीएससी-2003 का मामला अब भी अदालत में है,यही वजह है कि लोग अब पूछने लगे हैं क्या न्याय इतनी देर से मिलेगा कि उसका अर्थ ही खत्म हो जाए? या फिर यह मामला भी उन लंबी कानूनी लड़ाइयों में शामिल हो जाएगा,जिनका फैसला इतिहास में तो दर्ज होता है,लेकिन पीड़ितों के जीवन में नहीं?

'महाविद्रोह जारी रहेगा'-सिर्फ नारा नहीं,व्यवस्था पर सवाल है...

पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस लाइन की हो रही है,वह है उलगुलान (महाविद्रोह) जारी रहेगा...यह सिर्फ एक भावनात्मक वाक्य नहीं है,यह उस गुस्से,निराशा और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है,जो वर्षों से सिस्टम के खिलाफ जमा होता रहा,और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि पीएससी-2003 में क्या हुआ था,सवाल यह भी है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था इतने लंबे संघर्ष के बाद भी सच को अंतिम मंजिल तक पहुंचा पाएगी? फिलहाल लड़ाई जारी है...फैसला बाकी है...और सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए बैठे लोग अब भी यही कह रहे हैं–'न पद चाहिए...न पैसा... सिर्फ न्याय चाहिए।'

दूर-दराज से आने वाले छात्रों के लिए मुसीबत बना ION Digital Zone सरोना

CUET समेत बड़ी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी और परिजन बेहाल....
न पानी,न बैठने की व्यवस्था,भीषण गर्मी में घंटों सड़क किनारे इंतजार

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,15 मई 2026 (घटती-घटना)।

राजधानी रायपुर के सरोना स्थित ION Digital Zone एक बड़ा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र माना जाता है,जहां CUET, JEE, NEET, SSC,रेलवे,बैंकिंग,CAT, GATE और विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं। हर परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी यहां पहुंचते हैं। लेकिन बड़े दावों और आधुनिक व्यवस्था के बीच इस परीक्षा केंद्र के बाहर की जमीनी हकीकत अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दूर-दराज जिलों और दूसरे राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को यहां भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर CUET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के दौरान स्थिति और भी बदहाल दिखाई देती है।

अभ्यर्थी अंदर,परिजन बाहर परेशान : परीक्षा देने पहुंचे छात्र तो सेंटर के भीतर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले माता-पिता और परिजनों के लिए बाहर कोई समुचित व्यवस्था नजर नहीं आती। भीषण गर्मी में घंटों तक लोगों को सड़क किनारे खड़े रहना पड़ता है। कई परिजनों का कहना है कि सेंटर के बाहर न पर्याप्त छांव की व्यवस्था है,न पीने के पानी की और न ही बैठने के लिए कोई स्थायी इंतजाम। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ आने वाले परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।

सुबह से शाम तक सड़क किनारे इंतजार...

CUET जैसी परीक्षाओं में कई शिफ्ट होने के कारण अभ्यर्थियों को घंटों पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में उनके साथ आए परिजन सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक सड़क किनारे समय बिताने को मजबूर रहते हैं। कई लोग अपने साथ चादर, पानी की बोतल और खाने का सामान लेकर पहुंचते हैं,क्योंकि आसपास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गर्मी के कारण कई अभिभावकों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

परीक्षा केंद्र बड़ा,लेकिन बाहर अव्यवस्था

ION Digital Zone Sarona को रायपुर के प्रमुख CBT परीक्षा केंद्रों में गिना जाता है। सेंटर प्रबंधन के अनुसार यहां हजारों अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, CCTV, UPS बैकअप, वॉशरूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब एक ही दिन में हजारों परीक्षार्थियों का आना तय रहता है, तो उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती।

ट्रैफिक और पार्किंग भी बनी समस्या : परीक्षा के दिनों में सेंटर के आसपास भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क किनारे बड़ी संख्या में वाहन खड़े होने से आवागमन प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परीक्षा शुरू और समाप्त होने के समय सरोना मार्ग पर लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

दूर-दराज से पहुंचते हैं अभ्यर्थी : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर,जगदलपुर, कोरिया,जशपुर,बिलासपुर,कांकेर, राजनांदगांव और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में छात्र यहां परीक्षा देने पहुंचते हैं। कई अभ्यर्थी रातभर ट्रेन और बस से सफर कर सुबह सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा केंद्र के बाहर मूलभूत सुविधाएं न मिलें तो परेशानी और बढ़ जाती है।

पहले भी उठते रहे हैं सवाल

परीक्षा केंद्र में भीड़, गर्मी,बैठने की कमी और अव्यवस्था को लेकर पहले भी सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थियों द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं। कई लोगों ने परीक्षा के दिनों में बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं की मांग उठाई थी। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है।

राज्य शासन और प्रशासन से मांग

अभिभावकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य शासन और जिला प्रशासन को ऐसे बड़े परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

विशेष रूप से:-

- परिजनों के लिए प्रतीक्षालय
- पेयजल व्यवस्था
- अस्थायी शेड और बैठने की सुविधा
- ट्रैफिक नियंत्रण
- मेडिकल सहायता
- मोबाइल टॉयलेट
- जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

जनहित से जुड़ा मामला

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर केवल ऑनलाइन व्यवस्था और कंप्यूटर लैब पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। हजारों परिवारों की सुविधा और सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य शासन,जिला प्रशासन और परीक्षा आयोजन एजेंसियां इस ओर ध्यान देती हैं या फिर हर परीक्षा में अभ्यर्थी और उनके परिजन इसी तरह परेशान होते रहेंगे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)